04 - तेल की राजनीति और भारत की स्वायत्तता

05 - मेरी आवाज़ ही पहचान है

A Daily News Magazine
इंदौर
शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026

06 - म.प्र. राज्य मिलेट्स मिशन योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कृषि मेले...

07 - प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में शिविर आयोजित कर...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 133, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews


प्रसंगवश

# अमेरिका-बांग्लादेश ट्रेड डील से भारत की चिंता क्यों बढ़ी?

**राघवेंद्र राव**

विगत 9 फरवरी को अमेरिका और बांग्लादेश ने रेसिप्रोकल टैरिफ़ (परस्पर शुल्क) से जुड़े एक व्यापार समझौते पर दस्तख़त किए। बांग्लादेश की तरफ से वाणिज्य सलाहकार शेख बशीरुद्दीन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने और अमेरिका की तरफ से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमीसन ग्रीयर ने समझौते के दस्तावेज़ पर दस्तख़त किए। इस समझौते पर बातचीत पिछले साल अप्रैल से लगभग नौ महीने तक चली।

समझौते के तहत अमेरिका ने बांग्लादेश पर रेसिप्रोकल टैरिफ़ को 19 फ़ीसदी तक कम करने पर सहमति जताई है। ये टैरिफ़ पहले 37 फ़ीसदी था और इसे पिछले साल अगस्त में घटाकर 20 फ़ीसदी किया गया था।

इसके अलावा अमेरिका ने यह व्यवस्था बनाने पर भी सहमति दी है कि बांग्लादेश से कुछ विशेष टेक्सटाइल और परिधान जो अमेरिकी कपास और कृत्रिम रेशे से बने होंगे, उन्हें अमेरिकी बाज़ार में शून्य शुल्क पर प्रवेश मिलेगा।

इस समझौते के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार को भारत की कपड़ा और सूत कंपनियों के शेयरों में तेज़ गिरावट आई। समझौते के बाद ये चिंताएं जताई जा रही हैं कि अमेरिका के कपड़ों के बाज़ार में भारत की स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है। इसकी वजह निवेशकों का अमेरिका-बांग्लादेश टैरिफ़ समझौते और अमेरिकी कपास के इस्तेमाल से जुड़ी अहम शर्त के असर को लेकर चिंतित होना है।

कपड़ों के निर्यात में भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा रही है। इस नए व्यापार समझौते के बाद ये चिंताएं जताई जा रही हैं कि समझौते के कुछ प्रावधान भारत के लिए झटका साबित हो सकते हैं। चिंता यह है कि बांग्लादेश धीरे-धीरे भारतीय कच्चा माल छोड़कर अमेरिकी कपास का इस्तेमाल करने लग सकता है जिसका सीधा असर भारत के कपास किसानों और धागा उद्योग पर पड़ सकता है। फ़िक्र इस बात की भी है कि ज़ीरो टैरिफ़ का फ़ायदा मिलने की वजह से बांग्लादेश के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में और सस्ते हो जाएंगे जिससे भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए मुक़ाबला और मुश्क़िल हो जाएगा।

इस समझौते का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। एक्स पर खेड़ा ने लिखा, 'मास्टरस्ट्रोक किंग ने भारत के कपड़ा उद्योग और कपास किसानों, दोनों को बर्बाद कर दिया है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए नए 'पारस्परिक व्यापार समझौते' की सतह पर संरचना भारत जैसी ही दिखती है (19% बेस टैरिफ़), लेकिन बारीकियां पूरा खेल बदल देती हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए 'ज़ीरो ड्यूटी' प्रावधान जोड़ा है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि बांग्लादेश को अमेरिकी कपास और इनपुट्स का इस्तेमाल करना होगा। भारतीय टेक्सटाइल अब प्रतिस्पर्धी नहीं रहेंगे। भारत 18 फ़ीसदी शुल्क पर अटका रहेगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश केवल अमेरिकी कच्चा माल लेकर शून्य फ़ीसदी शुल्क पर अमेरिकी बाज़ार में प्रवेश कर सकता है। यह कम मार्जिन वाले उद्योग में एक अपार मूल्य-अंतर पैदा करता है।

यह समझौता बांग्लादेश को प्रभावी रूप से अमेरिकी कपास के पक्ष में भारतीय धागा छोड़ने के लिए प्रलोभन देता है।

ख़बरों के मुताबिक़ साल 2024-25 में भारत ने बांग्लादेश को 1.47 अरब डॉलर (570 मिलियन किलो) का सूती धागा निर्यात किया। बांग्लादेश भारतीय धागे का सबसे बड़ा ख़रीदार है। बांग्लादेश के लगभग 20 फ़ीसदी कपड़ा निर्यात और भारत के 26 फ़ीसदी सूती परिधान निर्यात अमेरिका को जाते हैं।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने कहा कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते का 'तुरंत असर भारतीय सूती धागे पर पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश अब अमेरिकी कपास ख़रीदकर अपनी टेक्सटाइल मिलों में धागा तैयार कर सकता है। प्रोफ़ेसर हर्ष वी पंत नई दिल्ली स्थित ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। वह कहते हैं, 'मुझे लगता है कि इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका अपने कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, और इससे बांग्लादेश को जो फ़ायदे मिलेंगे- और यह देखते हुए कि अमेरिका बहुत लेन-देन वाली नीति अपनाता है- बांग्लादेश के लिए उस रास्ते पर न जाना मुश्किल होगा। यह ट्रंप प्रशासन के लिए इस सौदे की सफलता का एक अहम पैमाना भी बनेगा। और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, एक तरह का डोमिनो इफ़ेक्ट।'

'जाने-माने अर्थशास्त्री प्रोफ़ेसर बिस्वजीत धर कहते हैं कि हमारे यहां बातें चल रही थीं कि हमें ज़्यादा नुक़सान नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश का टैरिफ़ ज़्यादा है और ख़ासकर कपड़ों के मामले में हमें नुक़सान नहीं होने वाला है और अमेरिका के साथ जो भारत की ट्रेड डील हुई है उससे फ़ायदा होगा... वह बात अब रही नहीं क्योंकि बांग्लादेश पर टैरिफ़ भले ही एक फ़ीसदी घटा हो लेकिन जो उनके कपड़ों को बिना टैरिफ़ अमेरिका में प्रवेश मिलेगा उससे भारत पर असर पड़ेगा।'

भारत जो यार्न बेचता था उसका एक बहुत बड़ा बाज़ार बांग्लादेश में था। बांग्लादेश अब अमेरिका से यार्न ख़रीदेगा और हमारी यार्न इंडस्ट्री के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इससे ढाका को कुछ हाई-वैल्यू वाले सेगमेंट में बढ़त मिल सकती है। लेकिन भारत के पास अन्य क्षेत्रों में कई फ़ायदे हैं, भले ही यह फ़ायदा टेक्सटाइल क्षेत्र में न हो, लेकिन इसे दूसरे सेक्टरों से जोड़ा जा सकता है।

सवाल यह भी उठ रहा है कि इस तरह के समझौते करने के पीछे अमेरिका की मंशा है क्या? प्रोफ़ेसर बिस्वजीत धर कहते हैं, 'देखिए अमेरिका एक तरह से हमारे जैसे देशों को कॉम्पीटीशन में डाल रहा है। अमेरिका की मंशा यह देखना है कि कौन कितना झुकेगा। अमेरिका चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। द्विपक्षीय समझौतों का ये सबसे बड़ा नुक़सान है। भारत के साथ बांग्लादेश की क़रीबी रणनीतिक साझेदारी रही है। अब उसमें बदलाव ज़रूर होगा। रिश्ता पहले से ही नाज़ुक है। अब बीच में अमेरिका आएगा और भारत और बांग्लादेश के बीच मुश्किल हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। अमेरिका चाहेगा कि वह अपना फ़ायदा ले ले और भारत और बांग्लादेश आपस में लड़ते रहें। इन मामलों में असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह फ़ैसले ज़मीन पर कैसे लागू होते हैं। 'पंत के मुताबिक़ कुल मिलाकर टैरिफ़ बढ़ ही रहे हैं. हां, तुलना में कुछ जगह कम भी हो सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका थोड़ा ज़्यादा संरक्षणवादी बनता जा रहा है। अमेरिकी बाज़ार ज़्यादा संरक्षणवादी हो रहा है और अमेरिकी उद्योगों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अंतिम नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि इन फ़ैसलों को कैसे लागू किया जाता है और यह टैरिफ़ बदलाव वास्तव में कैसे दिखते हैं। मेरा मानना है कि अब केस टू केस आधार पर पारस्परिक टैरिफ़ बदलाव से बचा नहीं जा सकता।'

**(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)**

# सबसे बड़ी रक्षा डील को 'डीएसी' की मंजूरी

### खरीदे जाएंगे 114 नए राफेल जेट, हो गया फैसला

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** भारत सरकार ने 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदने की मंजूरी दे दी है, इसके अलावा पहले से वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए फ्रांस के साथ स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की भी डील पर चर्चा की गई है।

इसके साथ ही अमेरिका से 6 पी-81 समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट के जौहर देखने के बाद सरकार और वायुसेना का भरोसा लगातार इस फ्रांसीसी फाइटर जेट पर बढ़ रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की एक बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रालय ने 114 राफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे दी है।

यह डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए में होने वाली है। क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसी के साथ इस बैठक में केवल राफेल फाइटर जेट को लेकर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि तमाम अन्य आधुनिक हथियारों के अधिग्रहण को लेकर भी बात की गई। इसमें मुख्य रूप से फ्रांस से स्कैल्प क्रूज मिसाइल और अमेरिका से पी-81 समुद्री निगरानी विमान और भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सुदर्शन रक्षा कवच के लिए एस-400 की रक्षा खरीद पर भी चर्चा हुई।

### राफेल्स के लिए चाहिए स्कैल्प क्रूज मिसाइल

भारतीय वायुसेना की तरफ से लगातार फाइटर जेट्स की कमी की बात उठाई जाती रही है। यहां तक की एयर चीफ भी इसको लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। राफेल के आने के बाद से सेना को मजबूती मिली है। ऐसे में इन विमानों के लिए फ्रांसीसी स्कैल्प मिसाइलों की जरूरत भी महसूस की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने फ्रांस से राफेल जेट्स के साथ-साथ बड़ी मात्रा में स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी खरीदने की मंजूरी दी है। फ्रांस से बढ़ते रक्षा सौदों के बीच भारत ने अमेरिका के साथ भी अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। डीएसी की बैठक में अमेरिका के साथ करीब 3 अरब डॉलर की रक्षा खरीद को मंजूरी देने पर सहमति बनने की संभावना है। इसमें छह पी-8 आई समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान खरीदने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है।

# वंदे मातरम् पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला

### मदनी बोले- ये मनमाना और एकतरफा

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। संगठन ने सरकार के आदेश को एकतरफा और मनमाना बताया। जमीयत के प्रेसीडेंट मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन की तरह ही सम्मान देना अनिवार्य कर दिया है।

### संस्थान द्वारा प्रकाशित 7 पुस्तकों का किया गया विमोचन

# शोध ऐसा हो, जो बदल दे सबकी सोच : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शोध अकादमिक गतिविधि मात्र नहीं, यह समाज और राष्ट्र की दिशा बदलने वाली शक्ति है। कोई भी शोध इतना उच्च कोटि का होना चाहिए जो हम सबकी सोच को एक नई दृष्टि, नई दिशा भी दे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी शोधार्थियों से आह्वान किया कि वे देश के विकास के लिए अपनी जिज्ञासा और रुचि के अनुसंधान क्षेत्रों में निर्भीक होकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे ही शोध विज्ञान और सभी वैज्ञानिक पद्धतियों का जनक है। मानवीय प्रज्ञा में जब वैज्ञानिक ज्ञान का समावेश हो जाता है, तब वह 'प्रज्ञान' का रूप ले लेती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के विज्ञान भवन में श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोधार्थी समागम (नेशनल रिसर्चर्स मीट) 2026 को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विज्ञान के विकास में ही देश का समग्र विकास निहित है। मध्यप्रदेश को शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शोध समाज के विकास का आधार है और इसे आधुनिक, परिष्कृत तथा परिमार्जित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शोधार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे परंपरागत धारणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि नवीन विचारों और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ ऐसे शोध प्रस्तुत करें, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शोध सिर्फ़ एक शैक्षणिक आवश्यकता नहीं, सामाजिक परिवर्तन और विकास का सशक्त माध्यम भी है।

### हमारी पीएचडी हमें ही समझ नहीं आती

राजधानी में आयोजित नेशनल रिसर्चर मीट के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक अलग ही अंदाज में नजर आए। दत्तोपंत ठेंगडी शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री और राजनेताओं के प्रति सामाजिक नजरिए पर जमकर चुटकी ली। सीएम ने कहा कि आज के दौर में हमने शोध को इतना क्लिष्ट (कठिन) कर दिया है कि वह बलिष्ठ होकर हम पर ही हावी हो गया है।

### राजनेता और पीएचडी... यह तो डबल आफत है

मुख्यमंत्री ने अपनी शोध यात्रा के संघर्ष को साझा करते हुए कहा, कई बार हमारी पीएचडी हमें ही मालूम नहीं पड़ती कि वो काहे के लिए है। यह और भी दिक्कत तब कर देती है जब कोई राजनेता पीएचडी करे। समाज में यह संकट जुड़ा है कि यदि राजनेता पीएचडी है, तो वह यह (नकल या शोध) कर ही नहीं सकता। राजनेता के साथ तो यह डबल आफत है।

### आयोजकों को नसीहत-अगली बार मेरा नंबर पहले रखना

कार्यक्रम में वक्ताओं के क्रम में सबसे अंत में भाषण के लिए बुलाने पर मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा- मुख्यमंत्री के नाते प्रशासनिक दृष्टि से मेरा सबसे अंत में बुलवाना इस बात पर मेरा ध्यान गया कि ये कार्यक्रम किसने बनाया है। इतने अच्छे वक्ताओं के भाषण के बाद आखिरी में मुझे बुला रहे हैं। इसे या तो ये अपनी एक त्रुटि मान लें कि इन सारे विषयों को रखने के लिए मुख्यमंत्री को कहां रखना चाहिए। ये एक संकट भी है लेकिन शोध संस्थान है तो ये सारे प्रयोग करने के लिए छूट भी है। सीएम ने अपने भाषण के अंत में फिर कहा इस आयोजन के उद्घाटन सत्र में आपने सुयोग्य अतिथि बुलाए, लेकिन अगली बार मुझे माफ करना, अगली बार मेरा नंबर पहली बार रख देना।

### शरद की सुबह

मैं चिड़िया से
प्यार करता हूँ
क्योंकि एक चिड़िया
मेरे अंदर है

मैं नदी से
प्यार करता हूँ
क्योंकि एक नदी
मेरे अंदर है

मैं ऋतुओं से
प्यार करता हूँ
क्योंकि एक ऋतु
मेरे अंदर है

मैं स्त्री से
प्यार करता हूँ
क्योंकि एक स्त्री
मेरे अंदर है

मैं बच्चों से
प्यार करता हूँ
क्योंकि एक बच्चा
मेरे अंदर है।

– दुर्गाप्रसाद झाला

# सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जारी किए नए दिशा निर्देश

### ● जमानत के लिए अब पूर्व अपराधों का खुलासा अनिवार्य

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जमानत की मांग करने वाले प्रत्येक आरोपित का यह दायित्व है कि वह जमानत संबंधी निर्णयों में एकरूपता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए हलफनामे के माध्यम से अपने पूर्व के अपराधों का उजागर करे। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि जमानत की मांग करने वाले आरोपित या आवेदक का यह दायित्व है कि वह न्यायिक विवेक के प्रयोग को सीधे प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को निष्पक्ष और पूर्ण व स्पष्ट रूप से उजागर करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना, छिपाना या चुनिंदा रूप से प्रकट करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और आपराधिक न्याय प्रशासन की नींव पर प्रहार करता है। पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि जमानत आवेदनों में प्राथमिकी संख्या और तिथि, संबंधित पुलिस थाने का नाम, जांच एजेंसी द्वारा लगाई गई धाराएं और कथित अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा आदि का उल्लेख होना चाहिए। अदालत ने कहा, इस अदालत के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले की एक प्रति सभी हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार जनरल को भेजें। हाई कोर्ट अपने नियम बनाने की शक्तियों के अनुरूप उचित प्रशासनिक निर्देश जारी करने या अपने-अपने नियमों में उपयुक्त प्रविधान शामिल करने की व्यवहार्यता की जांच कर सकते हैं।

### महाशिवरात्रि पर लाडले मशक दरगाह में होगी शिव पूजा

### ● सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया बड़ा फैसला

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक के अलंद में महाशिवरात्रि के दौरान लाडले मशक दरगाह परिसर और हिंदू संत राघव चैतन्य की समाधि के अंदर पूजा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि जब यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है, तो याचिकाकर्ता संविधान के आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट खलील अंसारी नाम के व्यक्ति की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें संपत्ति में हस्तक्षेप को रोकने और संपत्ति पर निजी बचाव पक्ष के कब्जे को रोकने के लिए किसी भी तरह की गैर-कानूनी प्रवेश, भीड़, जमावड़े को रोकने के साथ-साथ पूजा की इजाजत देने वाले किसी भी अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

### हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पवित्र स्थल

दरगाह 14वीं सदी के सूफी संत और 15वीं सदी के हिंदू संत से जुड़ी है और ऐतिहासिक रूप से दोनों की पूजा की साझा जगह रही है। हालांकि, 2022 में दरगाह पर धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद होने पर तनाव बढ़ गया, जिससे सांप्रदायिक अशांति फैल गई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील विभा दत्ता मखीजा ने कहा कि हाई कोर्ट पहले ही इस मामले पर फैसला कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता घोषित करने की मांग कर रहा है कि प्रॉपर्टी सही तरीके से नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है, जिस पर वक्फ ट्रिब्यूनल को फैसला करना है। मखीजा ने कहा कि इस मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं और बेंच से आग्रह किया कि इसे ऐसे ही मामलों के साथ टैग किया जा सकता है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

# सुबह सवेरे

इंदौर ■ शुक्रवार, 13 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

## जब तक नया टाइटल नहीं बताओगे, फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे

● सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, घूसखोर पंडत पर डायरेक्टर को फटकार

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** मनोज बाजपेयी की घूसखोर पंडत फिल्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर नीरज पांडे फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा टाइटल इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को क्यों बदनाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मेकर नीरज पांडे को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक आप हमें बदला हुआ टाइटल नहीं बताते, हम आपको फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने घूसखोर पंडत पर फिल्ममेकर नीरज पांडे से

कहा कि फिल्म का टाइटल नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म घूसखोर पंडत की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी पर केंद्र, बोर्ड और नीरज पांडे को नोटिस जारी किया है। बता दें कि बीते 03 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स ने अपने साल 2026 के लिए इंडिया प्लान का एलान किया। इसमें मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडत का एलान भी टीजर रिलीज करके किया गया। लेकिन इसकी टाइटल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर गए। इसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फिल्म में मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस ऑफीसर की भूमिका निभा रहे हैं। जिन्हें पुलिस महकमे में 'पंडत' कहा जाता है।

## चीन की दुखती रग के पास गरजे भारतीय सुखोई विमान

● ग्रिपेन लड़ाकू विमानों ने भी दिखाया जलवा, मलक्का स्ट्रेट से डरता है ड्रैगन

**नई दिल्ली/बैंकॉक (एजेंसी)।** मलक्का स्ट्रेट, जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है, वहां भारत ने थाईलैंड की वायुसेना के साथ ज्वाइंट ड्रील की है। भारतीय वायुसेना के एसयू-30 लड़ाकू विमानों ने थाईलैंड एयरफोर्स के ग्रिपेन लड़ाकू विमानों के साथ ड्रील की है। सबसे खास बात यहां पर ग्रिपेन लड़ाकू विमान है,

जिसका ऑफर स्वीडन की कंपनी साब ने भारत को दिया है। स्वीडिश कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपने मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए अपना ग्रिपेन लड़ाकू विमान का प्रस्ताव दिया है। क्या भारत, स्वीडिश फाइटर जेट को परखने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वायुसेना की तरफ से 10 फरवरी को कहा गया है कि भारतीय वायुसेना, रॉयल थाई एयर फोर्स के साथ एक ज्वाइंट इन-सीटू एयर एक्सरसाइज कर रही है। इस एक्सरसाइज से दोनों एयर फोर्स के बीच ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी।

# भाजपा सांसद का नोटिस-राहुल की सदस्यता खत्म हो

● कहा- वे देश को गुमराह कर रहे, रिजिजू ने स्पीकर चैंबर में हंगामे का वीडियो जारी किया

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** बजट पर चर्चा के दौरान गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल हंगामे के कारण नहीं चल सका। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सांसद प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। नारेबाजी भी होती रही। स्पीकर चेयर पर मौजूद केपी तेन्नेटी ने 7 मिनट के बाद ही सदन को स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। उधर, पीएम मोदी राज्यसभा में पहुंचे थे। इधर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव

लड़ने लाइफटाइम बैन लगाने की मांग की है। सब्सटेंसिव मोशन वह प्रपोजल है, जिस पर सदन सीधे चर्चा करके फैसला ले सकता है। इस मोशन में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि सदन किसी मुद्दे पर क्या फैसला ले। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी। हालांकि, 11 फरवरी के उनके भाषण के कुछ हिस्से हटा दिए जाएंगे।

### पीएम ने बजट पर सीतारमण की स्पीच की तारीफ की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने इस साल के बजट से देश के आर्थिक बदलाव में कैसे योगदान मिलेगा, इसकी पूरी तस्वीर दी है। कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमने स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की। सरकार चेयर पर पूरी तरह से दबाव डाल रही है कि विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका न दिया जाए। राहुल जी जो भी कहते हैं, उसे रिकॉर्ड से हटा देते हैं।

### पीयूष गोयल बोले- राहुल गांधी झूठ का पुलिंदा हैं

राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राहुल गांधी झूठ का पुलिंदा हैं। वह पूरी तरह से गलत जानकारी फैलाते हैं। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि यूएस-इंडिया ट्रेड डील में भारत के हितों और भारतीय किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। भारतीय किसानों के ज़्यादातर प्रोडक्ट, हमारी डेयरी, पोल्ट्री, चावल, गेहूं, सोयाबीन और मक्का, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, संतरा, सब्जियां, इथेनॉल, तंबाकू, मीट, दालें, बाजरा, रागी- किसानों का लगभग 90-95 फीसदी प्रोडक्ट यूएस ट्रेड डील से बाहर है और जो भारत की जरूरत है, जिसे हम आज भी इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे देश के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी चीजों को अमेरिका के लिए सोची-समझी रणनीति के तहत सोच-समझकर खोला है। एक तरह से किसानों के हितों में एक बहुत अच्छी यूएस ट्रेड डील हुई है, लेकिन राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठकर इसके बारे में झूठ बोलते है।

### सारस्वत अभिनंदन सम्मान

**उज्जैन।** धर्म के प्रखर प्रणेता, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं सनातन धर्म के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवर्तक, श्रीमद्भगवद्गीता के आध्यात्मिक शिखर पुरुष डॉ. तेज प्रकाश पूर्णानन्द व्यास को द्वितीय ज्योतिष परिचय समागम श्री गंगा उज्जैन में सारस्वत अभिनंदन सम्मान पत्र से विभूषित किया गया।

### आचार्य श्री संतोषदास जी (सतुआ बाबा) का उपमुख्यमंत्री ने किया आत्मीय स्वागत व अभिनंदन

**भोपाल।** महामंडलेश्वर काशी पीठ आचार्य श्री संतोषदास जी (सतुआ बाबा) का उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने अपने अमहिया (रीवा) निवास में आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य जी का सानिध्य एवं आशीर्वाद सदैव समाज को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। उप मुख्यमंत्री ने श्री सतुआ बाबा के साथ ईको पार्क स्थित कुंडलेश्वर मंदिर में भगवान आशुतोष का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने आचार्य जी को ईको पार्क की प्राकृतिक सुंदरता का अवलोकन कराया जिसकी संत श्री ने भूरि-भूरि प्रशंसा की।

## असम में रचा गया इतिहास हाईवे पर उतरा फाइटर जेट

● आकाश को चीरते हुए आया नजर, पीएम करेंगे उद्घाटन

**डिब्रूगढ़ (एजेंसी)।** भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने पूर्वोत्तर के पहले आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पर परीक्षण अभ्यास शुरू किया। भारतीय वायु सेना के टच-एंड-गो ऑपरेशन के पूर्ण पूर्वाभ्यास से पहले पहला राफेल विमान मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर उतरा। सुखोई-30 और राफेल लड़ाकू विमानों ने डिब्रूगढ़ के मोरान के आसमान में गर्जना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 फरवरी की यात्रा से पहले इस ऐतिहासिक हवाई प्रदर्शन को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सुखोई-30, राफेल लड़ाकू विमान, स्वदेशी तेजस जेट, हरक्यूलिस ट्रांसपोर्टर और एंटोनोव एएन-32 विमानों सहित उन्नत लड़ाकू विमानों ने मोरान में विशेष रूप से निर्मित 4.2 किलोमीटर लंबी राजमार्ग हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक-ऑफ का प्रदर्शन किया। सैन्य विमानन शक्ति की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों दर्शक हवाई अड्डे पर जमा हो गए, जिससे वे रोमांचित हो गए। एनएच-127 पर स्थित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के प्रमुख स्थानों पर छात्र, बच्चे और स्थानीय निवासी जमा हो गए। विशाल विमान के उतरते ही और फिर एक के बाद एक गर्जना करते हुए नीले आकाश में वापस उड़ जाने पर खुशी से झूम उठे और हाथ हिलाए।

## फिर घेरेगी ईडी, मुश्किल में फंसेंगे केजरीवाल!

● *समन अनदेखी मामले में निचली अदालत से राहत को देगी चुनौती*

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वह दिल्ली आबकारी शुल्क नीति मामले में एजेंसी के समन का पालन न करने के आरोप में अरविंद केजरीवाल को दो मामलों में बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देगी। ईडी ने समन की अनदेखी करने के मामले में अरविंद केजरीवाल की दोबारा कानूनी घेरेबंदी करने की तैयारी कर ली है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि वह दिल्ली आबकारी मामले में समन का पालन नहीं करने के आरोप में अरविंद केजरीवाल को दो मामलों में बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देगी। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। इसी साल 22 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग मामलों में बरी कर दिया था।

● कश्मीर से हिमाचल तक टेंशन में किसान! बढ़ गई हैं चिंताएं

## यूएस संग ट्रेड डील से संकट में 10000 करोड़ की इंडस्ट्री

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** पिछले साल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घाटी के सेब उत्पादकों को भरोसा दिलाया था कि वह सेब इम्पोर्ट को लेकर उनकी चिंताओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे लेकिन इस ट्रेड ने अब उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के सेब किसानों में चिंता बढ़ गई है।

किसानों को डर है कि अगर अमेरिकी सेब सस्ते दाम पर भारतीय बाजार में आने लगे, तो स्थानीय सेब की मांग और कीमत दोनों गिर सकती हैं। इस डील के तहत कई देशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क कम किया जा रहा है। पहले ज्यादा कीमत होने के कारण विदेशी सेब कम मात्रा में आते थे, लेकिन अब ड्यूटी कम होने से आयात बढ़ने का डर है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सेब उद्योग बहुत अहम है। हजारों परिवार सीधे या परोक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। ऐसे में अगर विदेशी सेब ज्यादा आए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर असर पड़ सकता है।

● **10,000 करोड़ रुपये की है सेब इंडस्ट्री**-बता दें कि सेब इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था, खासकर कश्मीर घाटी की इकॉनमी का आधार और रीढ़ है। घाटी देश के कुल सेब उत्पादन का 75 फीसदी पैदा करती है। आधिकारिक आंकड़ों के के मुताबिक घाटी में करीब 20 लाख मीट्रिक टन सेब पैदा होते हैं और इस सेब इंडस्ट्री की कीमत 10,000 करोड़ रुपये है। अधिकारियों का कहना है कि इस इंडस्ट्री में सीधे या अप्रत्यक्ष करीब 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल किसान संगठन सरकार से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब किसानों ने भारत-यूएस डील में खेती की उपज, खासकर सेब को शामिल करने के खिलाफ 12 फरवरी को बंद और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। कश्मीर के किसान भी परेशान हैं।

## पंजाब में बीजेपी दो पुराने साथी मिटा रहे दूरियां

### गवर्नर की पदयात्रा में कदमताल करते नजर आई टॉप लीडरशिप

**चंडीगढ़ (एजेंसी)।** पंजाब में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी जहां सरकार दोबारा बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं भाजपा अपना आधार बनाने की कोशिशों में जुटी है लेकिन भाजपा के लिए पंजाब की राह आसान नहीं है। ऐसे में पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से बिगड़ी बात बनाने के अंदरखाते प्रयास भी हो रहे हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल और भाजपा का गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद न तो किसी चुनाव में अकाली दल उभर पाया और न ही भाजपा। पिछले विधान सभा चुनाव और लोक सभा चुनाव में भी दोनों के बीच गठबंधन की चर्चाएं होती रहीं मगर बात नहीं बनी। अब एक बार फिर से दोनों दलों के एक होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बात को मंगलवार को और बल तब मिला, जब फिरोजपुर में पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने नशामुक्ति को लेकर पदयात्रा की, जिसमें दोनों दलों की टॉप लीडरशिप एक साथ कदमताल करती नजर आई। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा के साथ सुखबीर बादल भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। 2020 में गठबंधन टूटने के बाद यह पहला मौका था, जब दोनों दलों के नेता साथ थे।

● **डेरा ब्यास के बाबा बनेंगे गठबंधन के सूत्रधार!**- अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन में डेरा ब्यास मुखी की भूमिका अहम मानी जा रही है। इस यात्रा में डेरा ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो भी शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान स्कूल के बंद कमरे में डेरा मुखी, गवर्नर और भाजपा नेताओं की मीटिंग हुई, जिसको लेकर पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई। इसके बाद शाम को अकाली नेता बिक्रम मजीठिया भी डेरा मुखी से मिलने ब्यास पहुंचे। मजीठिया लगातार गठबंधन की पैरवी कर रहे हैं। 7 महीने से जेल में बंद अकाली नेता बिक्रम मजीठिया से सुबह उनकी मुलाकात हुई थी और दोपहर तक जमानत मिल गई थी।

● **नफा-नुकसान देख कर फैसला करेगा भाजपा हाईकमान**-अकाली दल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह भाजपा से गठबंधन करना चाहता है, क्योंकि यह गठबंधन पहले भी पंजाब में सरकार बना चुका है। इस बात पर पंजाब भाजपा के नेता भी दो धड़ों में बंटे हुए हैं। एक धड़ा गठबंधन चाहता है मगर दूसरा नहीं। भाजपा हाईकमान भी पंजाब में विरोधी दलों की तैयारियों और उनके मुकाबले भाजपा संगठन की धरातल पर स्थिति व भावी संभावनाओं की समीक्षा और आकलन कर रही है। भाजपा-अकाली गठबंधन के नफा और नुकसान इन दोनों पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अंतिम फैसले में भले समय लग सकता है मगर राज्यपाल के साथ अकाली और भाजपा नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दोनों दलों के बीच सियासी कड़वाहट काफी हद तक कम जरूर हो गई है।

## भारत की सुरक्षा के लिए देंगे खतरनाक हथियार

● *भारत के साथ ट्रेड डील के बाद बदले अमेरिका के सुर*

**वाशिंगटन (एजेंसी)।** अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का शासन आने के बाद से भारत के साथ संबंधों में लगातार गिरावट आ रही थी। बात इस हद तक बिगड़ गई थी कि ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को तो भला-बुरा कहा ही और फिर टैरिफ भी थोप दिए। अब ट्रेड डील के बाद एक बार फिर से दोनों देशों से संबंधों में गर्मजोशी देखने को मिल रही है। अमेरिका की तरफ से भारत के साथ रक्षा और आर्थिक सहयोग का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग में एशियाई मामलों के सहायक सचिव पॉल कपूर ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों देश लगातार रक्षा संबंधी खरीद पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका और भारत लगातार अधिक हथियार प्रणालियों की खरीद पर काम कर रहे हैं। इनसे भारत की रक्षा क्षमता और भी ज्यादा मजबूत होगी और इसके साथ ही अमेरिका में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। कपूर ने इस बात की पुष्टि की है कि कई तरह के खतरनाक हथियार, जो कि भारत की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगे, इस वक्त दोनों देशों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी अधिकारी का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत की तरफ से 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है।

## कनक एवेन्यू में चोरी का प्रयास, 3 गिरफ्तार

**इंदौर।** लसूड़िया थाना क्षेत्र के कनक एवेन्यू कॉलोनी में चोरी का प्रयास करने वाले तीन शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो कार भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पुनः चोरी की नीयत से इलाके में घूम रहे थे, तभी घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया गया। 24 जनवरी की रात फरियादी अनिल जायसवाल के घर में नकाबपोश बदमाशों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर प्रवेश किया, लेकिन घरवालों के जागने पर आरोपी भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान की। गिरफ्तार आरोपियों भदर सिंह ग्रेवाल, थानसिंह और ध्यान सिंह ने लसुडिया क्षेत्र की कई कॉलोनियों में सूने मकानों से चोरी करना स्वीकार किया है। पूछताछ में अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड प्राप्त किया है। अन्य मामलों में संलिप्तता की जांच जारी है।

## रेलवे ट्रैक किनारे शव, गला रेतकर हत्या

**इंदौर।** बाणगंगा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक मजदूर का शव रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला। सूचना पर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने धारदार हथियार से हमले की आशंका जताई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डीसीपी जोन-3 राजेश व्यास के मुताबिक युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। उसके शरीर पर अन्य चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस लूट और आपसी विवाद के एंगल से जांच कर रही है। वहीं परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को सुबह करीब 8 बजे एमआर-4 रेलवे पटरी के पास शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान खोजराम पुत्र लखन नारगे निवासी छत्तीसगढ़ के रूप में की है। वह पोलो ग्राउंड क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करता था। जानकारी के अनुसार खोजराम नारगे दिन और रात दोनों शिफ्ट में काम करता था। बुधवार रात वह अपने कमरे पर नहीं पहुंचा था। इसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस मृतक के साथियों और फैक्ट्री से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है।

## हत्या के प्रयास में तीन गिरफ्तार

**इंदौर।** शहर में अपराधों पर सख्त नियंत्रण के निर्देशों के तहत पलासिया पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। बदमाश मूलतः खंडवा के रहने वाले हैं। फरियादी राजेश पिता शिवनारायण शर्मा निवासी गणेश नगर ने 9 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 फरवरी की रात वह अपने मित्र धर्मेंद्र के साथ बड़वानी प्लाजा स्थित फ्लैट पर गया था। इसी दौरान पास में रहने वाले पंकज पुरी, पंकज और शुभम कुमार ने बिना किसी कारण दरवाजा खटखटाकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि तीनों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और राजेश पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसे चोटें आईं। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 109(1), 115(2), 296(ए), 3(5) का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी ने टीम गठित की। टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया।

## पार्किंग से डॉक्टर के जेवर चोरी

**इंदौर।** तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक होटल की पार्किंग से डॉक्टर दंपति की कार का ताला खोले बिना जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। वारदात उस वक्त हुई जब दंपति होटल में इंटरव्यू के लिए गए थे और कार की चाबी होटल स्टाफ के पास थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, फरियादी डॉक्टर अदिति पाराशर निवासी उज्जैन, अपने पति पवित्र के साथ इंटरव्यू के सिलसिले में होटल सरोवर पोर्टिको आई थीं। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी सोने की चेन और जेंट्स अंगूठी कार की डिक्की के भीतर बने ग्लव बॉक्स में रख दी थी। इसके बाद, उन्होंने होटल की वैले पार्किंग सुविधा का उपयोग करते हुए कार की चाबी वहां मौजूद कर्मचारी को सौंप दी। जब डॉक्टर अदिति इंटरव्यू खत्म कर वापस लौटीं और कार की डिक्की चेक की तो उनके होश उड़ गए। जेवरात के डिब्बे वहां मौजूद थे। आरोपियों ने इतनी सफाई से चोरी को अंजाम दिया कि केवल खाली डिब्बियां ही मौके पर मिलीं। घटना के बाद पीड़िता ने तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिसके पास कार की चाबी उपलब्ध थी। वहीं, पुलिस ने होटल के पार्किंग स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी है।

## साइबर थाने में धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज

**इंदौर।** शहर में साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में द्वारकापुरी और क्राइम ब्रांच थाना क्षेत्रों में दो अलग-अलग ठगी की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहला मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। गुमास्ता नगर निवासी मनीष कुमार श्रीवास्तव एसबीआई के एटीएम पर पैसे निकालने पहुंचे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने धोखे से उनका एटीएम कार्ड बदल लिया। बाद में उसी बदले गए कार्ड के जरिए उनके बैंक खाते से रकम निकाल ली गई। जब तक उन्हें इस बात की जानकारी मिली, तब तक खाते से पैसे निकल चुके थे। दूसरा मामला क्राइम ब्रांच थाना क्षेत्र का है, जहां मेघा गर्ग ने निवेश के नाम पर ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, चेन्नई निवासी वचिनाथन थंगवेल ने खुद को कंपनी का डायरेक्टर बताकर उन्हें निवेश का झांसा दिया और बड़ी रकम ले ली। आरोपी ने लाभ का आश्वासन दिया था, लेकिन न तो कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम वापस की गई। पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है।

# फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हड़पने वाला पकड़ाया

### दो फरार आरोपी पकड़े, 3.62 करोड़ की ठगी पकड़ी

**इंदौर।** कृषि भूमि के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फरार चल रहे दो मुख्य आरोपियों चंदन कीर और मेहरबान सिंह कीर को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले प्रवीण पूनमचंद और प्रवीण सिसोदिया को भी जेल भेजा जा चुका है। एडिशनल डीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया ने बताया कि विशाल सिंह की शिकायत पर जांच शुरू हुई थी। आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत करोड़ों की कृषि भूमि के फर्जी दस्तावेज, कूटरचित अनुबंध पत्र और एक नकली कॉलोनी का नक्शा तैयार किया। जमीन से जुड़े सिविल विवाद के लंबित रहते हुए ही उसे तीसरे पक्ष को बेचकर करीब 3.62 करोड़ रुपये की ठगी की गई। तकनीकी साक्ष्य और साइबर टीम की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेक बुक व फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। मामले में कुल छह आरोपी नामजद हैं। पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

# आनंद बाजार रोड पर 8 स्टोरी मल्टी लेवल पार्किंग, अप्रैल से शुरू करने की तैयारियां

**इंदौर।** शहर में बढ़ते ट्रैफिक के साथ कार पार्किंग न होना भी बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग घर से बाहर निकलने से पहले पार्किंग मिलेगी या नहीं, इस बारे में विचार करते हैं। जल्द ही इस समस्या का समाधान 8 स्टोरी मल्टी लेवल कार पार्किंग के रूप में मिलने वाला है। यह पार्किंग आनंद बाजार रोड पर अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है। यह आधुनिक 8 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग स्ट्रक्चर है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम पर आधारित है। इस पार्किंग में एक साथ लगभग 150 कारें और लगभग इतने ही दोपहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे। इसकी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस है और यहां ऑटोमेटेड एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। इसका मतलब है कि आप पैसे देकर सीधे अपनी गाड़ी पार्क करके जा सकते हैं और आकर ले सकते हैं। इसे बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर बनाया जा रहा है. इसे एजेंसी बना रही है। वह कुछ सालों तक इसका ऑपरेशन चलाएगी,

### शहर में गाड़ी कहां खड़ी की जाएगी इस समस्या का हल निकाल लिया

उसके बाद निगम को हस्तांतरित कर देगी। अभी सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। पुलिस भी चालानी कार्रवाई करती नजर आती है।

**2025 में शुरू हुआ था निर्माण-** ग्रेटर कैलाश के ठीक सामने और उसके आसपास की जमीन पर बन रही इस मल्टी लेवल कार पार्किंग को बनाने का काम 2025 में शुरू हुआ था। हालांकि, यह काफी धीमी गति से चल रहा है। लेकिन, हाल ही में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यहां का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इसी साल अप्रैल से यह पार्किंग शुरू हो जाएगी। पार्किंग शुरू होने के बाद मुख्य सड़क पर किनारे खड़ी होने वाली गाड़ियों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसे फुटपाथ पर चलने वालों के लिए फ्री किया जाएगा।

### अन्य मार्गों पर भी पार्किंग

इंदौर नगर निगम की योजना है कि इसी तरह की कई पार्किंग राजवाड़ा, विजयनगर, भंवरकुआं जैसे मार्गों पर भी बनाई जाए, ताकि सड़क पर खड़ी गाड़ियों की वजह से जाम की स्थिति न बने। पूरी तरह से पार्किंग तैयार होने के बाद लोगों को पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे न केवल सड़क पर जाम से छुटकारा मिलेगा, बल्कि लोगों को आसानी से पार्किंग की सुविधा भी मिल पाएगी।

# श्रवण यंत्र प्रकरण में उपभोक्ता को राशि वापसी एवं क्षतिपूर्ति के निर्देश

### उपभोक्ता के हित में इंदौर उपभोक्ता आयोग का महत्वपूर्ण आदेश!

**इंदौर।** जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, इंदौर की सदस्य डॉ. निधि बारंगे (इंदौर-एक) ने श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) की आपूर्ति एवं सेवा में कमी से संबंधित एक प्रकरण में उपभोक्ता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया। आयोग ने श्रवण यंत्र की गुणवत्ता में खामी तथा शिकायत के निराकरण में लापरवाही को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 'सेवा में कमी' मानते हुए विपक्षी पक्ष को राशि वापसी एवं क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार परिवादी द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं विपक्षी पक्ष के आश्वासन पर 73 हजार मूल्य का श्रवण यंत्र क्रय किया गया था। परिवादी का कहना था कि यंत्र कान में सही ढंग से फिट नहीं हुआ, जिससे उन्हें अत्यधिक दर्द, असुविधा एवं मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ा। परिवादी द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा यंत्र को केवल सुधारने का प्रयास किया गया, किंतु समस्या का स्थायी

समाधान नहीं हो सका। इसके बाद परिवादी ने श्रवण यंत्र की राशि वापस करने की मांग की, परंतु निर्धारित समय में राशि लौटाई नहीं गई।

### दी गई सेवा संतोषजनक नहीं

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथ-पत्रों एवं तर्कों के सूक्ष्म परीक्षण के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि परिवादी को अपेक्षित एवं संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं की गई। आयोग ने माना कि श्रवण यंत्र की फिटिंग एवं कार्यक्षमता में कमी तथा शिकायतों के बावजूद समाधान न होना स्पष्ट रूप से सेवा में कमी को दर्शाता है।

### राशि व अन्य व्यय लौटाएं

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, इंदौर की सदस्य डॉ निधि बारंगे ने अपने अंतिम आदेश में विपक्षी पक्ष को निर्देश दिए कि वह आदेश की तिथि से 45 दिन के भीतर परिवादी को श्रवण यंत्र की पूरी राशि 73 हजार रुपए परिवाद प्रस्तुति की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटाए। इसके अतिरिक्त आयोग ने मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के लिए पाँच हजार रुपए तथा वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

## साकेत नगर और तिलक नगर में महापौर ने विकास के कार्य देखे

### सड़क, जलापूर्ति और सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर निर्देश

**इंदौर।** साकेत नगर एवं तिलक नगर क्षेत्र में चल रहे बुनियादी ढांचा विकास कार्यों ने सोमवार को गति पकड़ी, जब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम जोन क्रमांक-10 में विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा की समीक्षा करना रहा। महापौर के साथ विधायक महेंद्र हार्डिया, नगर आयुक्त क्षितिज सिंघल, एमआईसी सदस्य, क्षेत्रीय पार्षद एवं वरिष्ठ निगम अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के

दौरान महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय में पूर्ण हों और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। महापौर ने साकेत नगर के पास स्थित शासकीय खदान भूमि का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को भूमि स्वामित्व की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि भूमि नगर निगम की है तो वहां जनोपयोगी सुविधाओं के लिए सुनियोजित विकास किया जाए। इसके बाद श्रीकृष्ण पब्लिक स्कूल से महावीर बाग जल टंकी तक निर्माणाधीन 370 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी सड़क का निरीक्षण किया गया, जिसकी लागत लगभग 2.27 करोड़ है। महापौर ने कार्य में तेजी लाने और यातायात व नागरिकों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुनियोजित सड़क और जलापूर्ति विकास निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

## जुपिटर हॉस्पिटल में बम थ्रेट ड्रिल

**इंदौर।** शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस ने बुधवार को ज्यूपिटर विशेष हॉस्पिटल में बम थ्रेट मॉक ड्रिल आयोजित कर सुरक्षा इंतजामों की परख की। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में शहर के प्रमुख संस्थानों में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आरके सिंह,पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं सुरक्षा) राजेश व्यास तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रमोद सोनकर के मार्गदर्शन में बीडीडीएस टीम ने बुधवार को यह अभ्यास किया। बीडीडीएस प्रभारी खालिद मुश्ताक के नेतृत्व में टीम ने अस्पताल स्टाफ के साथ मिलकर लावारिस संदिग्ध वस्तु मिलने पर की जाने वाली कार्रवाई का प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स, सुरक्षाकर्मियों व स्टाफ को आपातकालीन स्थिति में क्या करें और क्या न करें, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई।

# विवाद में बाउंसर की हत्या करने वाले 4 बदमाशों को पकड़ा गया

### निकलते समय कंधा टकराने की बात पर हुआ था झगड़ा

**इंदौर।** चाय पीने के बाद बाहर निकलते समय मृतक का दोस्त का कंधा एक बदमाश से टकरा गया। बदमाश ने युवक को ठीक से चलने की बात की। इस पर युवक ने कहा गलती हो गई। तभी बदमाश ने अपने तीन अन्य साथियों को बुलाया और गाली गलौज की। युवक ने गाली देने से मना किया तो उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान युवक करण (दोस्त) ने कॉल कर अपने दो अन्य साथी गोलू और हरिओम को बुला लिया। गोलू और हरिओम वहां पहुंचे और बदमाशों को समझाने लगे, तभी आवेश में आकर बदमाशों ने बीयर की बोतल से गोलू और हरिओम पर सिर पर हमला कर दिया और मौके से भाग निकले। हमले में घायल हरिओम और गोलू को दोस्त करण अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां गोलू पिता चेनसिंह रघुवंशी (28) निवासी

गुलमोहर कालोनी कनाड़िया रोड ने दम तोड़ दिया। जबकि, हरिओम की हालत में सुधार है। घटना विजयनगर थाना अंतर्गत पीयू 4 में मंगलवार रात 11 बजे हुई। गोलू कैफे संचालक होने के साथ बाउंसर भी है।

### घायल प्राइवेट नौकरी में

हरिओम भी पीयू 4 स्थित ऑफिस में नौकरी करता है। सहायक पुलिस आयुक्त पराग सैनी ने बताया कि फरियादी करण की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 115(2), 296 (ए), 3(5), 351 (3), धारा 103 का केस दर्ज कर लिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत टीम को मौके पर रवाना किया गया। टीम ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस ने विजयनगर क्षेत्र में घूम रहे अखिलेश पिता प्रकाश वासरे निवासी प्रकाश चंद्र सेठी नगर, अमोघ रैदास पिता मोहन प्रसाद रैदास निवासी विराट नगर, आकाश पिता जितेंद्र कदम निवासी प्रकाश चंद्र शेट्टी नगर तथा वरुण पिता राकेश श्रीवास निवासी मयूर नगर को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी प्राइवेट नौकरी करते हैं, नशे के आदी है। पूछताछ में पता चला कि वे अक्सर रात में घुमते हैं। इस दौरान कई बार मारपीट कर चुके हैं।

# अवैध शराब की तस्करी पकड़ाई 60 हजार की मदिरा, वाहन जब्त

### गीता भवन क्षेत्र में आबकारी टीम की कार्रवाई, प्रकरण दर्ज

**इंदौर।** सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देशानुसार 10 फरवरी को आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई की। कंट्रोल रूम प्रभारी देवेश चतुर्वेदी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक आशीष कुमार जैन (वृत्त आंतरिक क्षेत्र क्रमांक-01) की टीम ने गीता भवन क्षेत्र में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान दो पहिया वाहन (एमपी 09 एसएस 1272) सफेद रंग की एक्टिवा से परिवहन की जा रही 2 पेटी (100 पाव) देशी प्लेन मदिरा बरामद की गई।

मदिरा को वाहन सहित जब्त कर आरोपी रवि पिता नंदकिशोर महावर (37), निवासी विनोबा नगर, इंदौर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जप्त मदिरा व वाहन का कुल बाजार मूल्य लगभग 60 हजार रुपये आंका गया है। कार्रवाई में आरक्षक निहाल सिंह बुंदेला, मुकेश रावत, विपुल खरे, वीरेन्द्र पटेल, मुकेश चौहान, विनीता नागराज

एवं नर्मदा अलावा का सराहनीय योगदान रहा।

### ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार

शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के अभियान के तहत थाना एरोड्रम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ब्राउन शुगर की डिलीवरी देने से पहले ही एक तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 08.75 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ?87,000 बताई जा रही है, तथा एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में रविवार की रात लगभग 1.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने गणेश धाम,सुखदेव विहार कॉलोनी के पास दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी सुमित पथरोड़ (24) निवासी पंचवटी नगर इंदौर के पास से मादक पदार्थ बरामद हुआ। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना जारी है।

## युवती ने बयान के बाद चौकी के बाहर जहर खाया, स्थिति ठीक

### कब्जा नहीं देने की प्रॉपर्टी ब्रोकर की शिकायत करने गई

**इंदौर।** शिकायत पर बयान दर्ज करा रही युवती अचानक पुलिस चौकी के बाहर निकली और आत्महत्या की नीयत से जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे राहगीर और परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत सामान्य बनी हुई है। युवती ने प्रापर्टी ब्रोकर पर कार्रवाई करना चाहती थी। जहर खाने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। घटना बुधवार दोपहर तीन बजे की है। बाणगंगा पुलिस ने बताया कि पेनजॉन कॉलोनी (बाणगंगा) निवासी तनीषा जगताप और 20 अन्य लोगों को सांवेर रोड पर मनीष धारकुंडे निवासी भागीरथपुरा ने प्लाट बेचे थे। प्लाट के एवज में सभी से अलग-अलग पैसे (करीब 50 लाख से अधिक) ले लिए थे। प्लॉट की किस्त पूरी होने के बाद जब तनीषा ने रजिस्ट्री के साथ कब्जा देने की बात कही तो ब्रोकर आनाकानी करने लगा। लगातार कॉल आने के बाद ब्रोकर ने मोबाइल बंद कर लिया। इसके बाद पीड़ित लोग ब्रोकर के घर भी पहुंचे, लेकिन वहां से कोई संतुष्टि भरा जबाव नहीं मिला तो मंगलवार को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई।

**गिरफ्तारी का बनाने लगी दबाव-** शिकायत के दूसरे दिन चौकी पर पदस्थ हेड कांस्टेबल कुलदीप पाल ने युवती को बयान दर्ज कराने बुलाया। युवती बयान के दौरान बार-बार आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कर रही थी। इस पर हेड कांस्टेबल ने आश्वस्त किया था कि बयान के बाद गिरफ्तार कर लेंगे। तभी वह नाराज हो गई और बाहर आकर चूहा मार दवा खा ली। तत्काल उसे पुलिस ने अस्पताल भिजवाया।

संपादकीय

# स्पीकर के प्रति अविश्वास !

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के 118 सांसदों द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की कोई संभावना नहीं है, परंतु यह आसंदी के प्रति विपक्ष के अविश्वास और सत्ता तथा प्रतिपक्ष के बिगड़ते रिश्तों का परिचायक जरूर है। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा होनी है। तब तक स्पीकर ओम बिरला ने आसंदी पर न बैठने का निर्णय किया है, जो उचित ही है। 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर से युक्त यह नोटिस विगत मंगलवार को लोकसभा के महासचिव को सौंपा गया। सरकार के लिए राहत की बात इतनी है कि अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर भी विपक्ष एकजुट नहीं है। उधर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के अनुसार स्पीकर को हटाने के लिए यह नोटिस संविधान के अनुच्छेद 94-सी के तहत लोकसभा सचिवालय को दिया गया है। जिसमें स्पीकर पर खुलेआम पक्षपात का आरोप है। नोटिस के मुताबिक स्पीकर ने विपक्ष के आठ सांसदों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया है। उन्हें केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए दंडित किया जा रहा है। कई मौकों पर विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने की अनुमति ही नहीं दी गई, जबकि यह उनका मौलिक अधिकार है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि स्पीकर लोकसभा के नियमों के संरक्षक हैं, जिन पर संसदीय गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने ही सदन में ऐसा बयान दिया, जो एक तरह से सांवैधानिक पद का अपमान है। इस नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में कांग्रेस, डीएमके, सपा के सांसद शामिल हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी के हस्ताक्षर नोटिस पर नहीं हैं। इस बीच स्पीकर बिरला ने विपक्ष के नोटिस पर लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को निर्देश दिया है कि वे नोटिस की जांच करें और उस पर आगे उचित कार्यवाही करें। नियमों के तहत इस नोटिस की जांच की जाएगी। लोकसभा में विवाद की शुरूआत राहुल गांधी को स्पीकर द्वारा बोलने के अनुमति नहीं दिए जाने से हुई थी। स्पीकर का कहना था कि राहुल विषय पर बोलें। जहां तक स्पीकर को हटाने की बात है तो इसकी लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में लोकसभा स्पीकर (अध्यक्ष) को अनुच्छेद 94(सी) के तहत अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस देना जरूरी है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। जब सदन में इस पर चर्चा हो तब स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। लेकिन सदन में स्पीकर को हटाने के लिए सदन में कम से कम 272 वोटों की जरूरत होगी। चाहे सदन में कितने ही सांसद मौजूद अथवा गैरमौजूद हों। अगर लोकसभा में यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है, तो स्पीकर को तत्काल प्रभाव से पद छोड़ना पड़ता है। इसके साथ ही सदन को नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। हालांकि विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की कोई संभावना इसलिए नहीं है, क्योंकि उसके पास सांसदों की जरूरी संख्या नहीं है। देश में पहले भी तीन बार इसी तरह स्पीकर को हटाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन नाकाम रही। बावजूद इसके स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को वास्तव में सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि सरकार दूसरे रास्ते से कोशिश कर रही है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव वापस ले ले और सदन में इस पर चर्चा की नौबत ही न आए। और सरकार की साख भी बची रहे। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, यह देखने की बात है। क्योंकि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच लगभग संवादहीनता की स्थिति है।

# तेल की राजनीति और भारत की स्वायत्तता

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
लेखक स्तंभकार हैं।

**अगर हम ध्यान दें तो कुछ वर्षों में रूस भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस ने अपने तेल को भारी छूट पर बेचना शुरू किया, जिससे भारत जैसे देशों को सस्ता तेल उपलब्ध हुआ। भारत, जो अपनी कुल तेल आवश्यकता का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, के लिए ऊर्जा सुरक्षा और किफायती कीमतें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रूस से सस्ते तेल की खरीद ने भारत को घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और आर्थिक विकास को स्थिर बनाए रखने में सहायता की है। नई दिल्ली के दृष्टिकोण से ऊर्जा खरीद कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित से प्रेरित एक व्यावहारिक आर्थिक निर्णय है।**

वैश्विक राजनीति के बदलते परिदृश्य में भारत की ऊर्जा नीति केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वायत्तता की परीक्षा बन गई है। रूस से तेल आयात और अमेरिका के दबाव के बीच भारत जिस संतुलन की राह चुन रहा है, वह उसकी विदेश नीति, आर्थिक भविष्य और वैश्विक पहचान को नई दिशा देता है। यहां प्रश्न यह है कि भारत को पश्चिमी देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी नीति बदलनी चाहिए या अपनी स्वतंत्र ऊर्जा रणनीति पर दृढ़ रहना चाहिए, केवल आर्थिक निर्णय का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक प्राथमिकताओं और बदलती वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका से जुड़ा हुआ गहन मुद्दा है। यह बहस केवल तेल तक सीमित नहीं है, यह भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय हित और वैश्विक शक्ति संतुलन में उसकी स्थिति का प्रतीक बन चुकी है।

अगर हम ध्यान दें तो कुछ वर्षों में रूस भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस ने अपने तेल को भारी छूट पर बेचना शुरू किया, जिससे भारत जैसे देशों को सस्ता तेल उपलब्ध हुआ। भारत, जो अपनी कुल तेल आवश्यकता का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, के लिए ऊर्जा सुरक्षा और किफायती कीमतें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रूस से सस्ते तेल की खरीद ने भारत को घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और आर्थिक विकास को स्थिर बनाए रखने में सहायता की है। नई दिल्ली के दृष्टिकोण से ऊर्जा खरीद कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित से प्रेरित एक व्यावहारिक आर्थिक निर्णय है।

किन्तु भारत की यह व्यावहारिक नीति अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका रूस को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की नीति पर कार्य कर रहा है और चाहता है कि भारत भी रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करे। वाशिंगटन की यह अपेक्षा व्यापक पश्चिमी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रूस के विरुद्ध एकजुट वैश्विक मोर्चा बनाना है। लेकिन भारत की स्थिति नाटो देशों से मूलतः भिन्न है। यूरोप के विपरीत भारत ने ऐतिहासिक रूप से विविध विदेश नीति अपनाई है और किसी भी कठोर भू-राजनीतिक गुट का हिस्सा बनने से परहेज किया है। भारत की विदेश नीति की आधारशिला रणनीतिक स्वायत्तता रही है, जो उसे विभिन्न शक्ति केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखने की स्वतंत्रता देती है।

भारत पर दबाव केवल नैतिक या राजनीतिक तर्कों तक सीमित नहीं है, इसके आर्थिक और रणनीतिक पहलू भी हैं। अमेरिका ने संकेत दिया है कि यदि भारत रूसी तेल पर अत्यधिक निर्भरता बनाए रखता है तो व्यापारिक परिणाम सामने आ सकते हैं। साथ ही, अमेरिका भारत को मध्य पूर्व, अमेरिका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से तेल आयात बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। यद्यपि स्रोतों का विविधीकरण दीर्घकालिक दृष्टि से उचित रणनीति है, परंतु यह न तो सरल है और न ही कम खर्चीला। वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं से तेल

अक्सर महंगा होता है, और परिवहन लागत तथा रिफाइनरी अनुकूलता जैसी तकनीकी चुनौतियाँ भी इस प्रक्रिया को जटिल बना देती हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले भारत के लिए अचानक महंगे ऊर्जा स्रोतों की ओर झुकाव आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।

कुछ वर्षों की बात करें तो भारत और अमेरिका के संबंध पिछले दशकों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी साझेदारी, व्यापार, निवेश और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर साझा चिंताएँ, ये सभी भारत-अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अमेरिका भारत को इंडो-पैसिफिक रणनीति में एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखता है, जबकि भारत को अमेरिका से उन्नत तकनीक, निवेश और रणनीतिक समर्थन प्राप्त होता है। यह पारस्परिक निर्भरता भारत के लिए एक जटिल संतुलन की स्थिति पैदा करती है, जहाँ उसे अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत भी करना है और अपनी स्वतंत्र नीति क्षमता को भी बनाए रखना है, साथ ही रूस जैसे पुराने सहयोगियों से दूरी भी नहीं बनानी है।

भारत की विदेश नीति में रूस का स्थान ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन के क्षेत्र में रूस भारत का विश्वसनीय सहयोगी रहा है। आज भी भारत की सैन्य तकनीक और हथियार प्रणालियों का बड़ा हिस्सा रूसी मूल का है, जिससे रूस से अचानक दूरी बनाना न केवल कठिन बल्कि रणनीतिक रूप से जोखिमपूर्ण भी है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक अनिश्चितताओं के समय रूस द्वारा सस्ते तेल की आपूर्ति ने भारत और रूस के आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया है। भारत के लिए रूस के साथ संबंध बनाए रखना भावनात्मक कारणों से नहीं, बल्कि ठोस रणनीतिक गणनाओं से जुड़ा हुआ है।

वैश्विक परिदृश्य भी इस मुद्दे को और जटिल बना देता है। दुनिया धीरे-धीरे एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहाँ कोई एक शक्ति अकेले नियम तय नहीं कर सकती। भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया जैसे उभरते देश अपनी नीतियों को वैचारिक दबाव के बजाय राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करने का अधिकार तेजी से स्थापित कर रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत द्वारा पश्चिमी निर्देशों का अंधानुकरण न करना उसकी संप्रभु शक्ति बनने की आकांक्षा का प्रतीक माना जा सकता है। यह भारत के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वह किसी भी महाशक्ति का अधीन सहयोगी बनने के बजाय स्वतंत्र वैश्विक अभिनेता बनना चाहता है।

फिर भी भारत वैश्विक शक्ति राजनीति की वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकता। पश्चिमी अपेक्षाओं की अत्यधिक अवहेलना से आर्थिक या कूटनीतिक नुकसान हो सकता है, जबकि अत्यधिक अनुपालन भारत की स्वतंत्र पहचान को कमजोर कर सकता है। चुनौती यह है कि भारत ऐसी संतुलित रणनीति विकसित करे, जो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करे, आर्थिक विकास को बनाए रखे और सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। इसके लिए केवल कूटनीतिक कौशल ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार भी आवश्यक हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, घरेलू ऊर्जा उत्पादन, और आधुनिक बुनियादी ढाँचे का विकास।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ती पहल इस दुविधा से निकलने का एक संभावित मार्ग प्रस्तुत करती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश भारत की ऊर्जा संरचना को धीरे-धीरे बदल रहा है। आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके भारत भविष्य में बाहरी दबावों से स्वयं को अधिक सुरक्षित बना सकता है। हालांकि, हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जो तत्काल रूप से कच्चे तेल की आवश्यकता को समाप्त नहीं कर सकती। उद्योग, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों में तेल की भूमिका अभी भी अपरिहार्य बनी हुई है। रूस से तेल आयात और अमेरिका के दबाव के बीच भारत की स्थिति एक व्यापक प्रश्न का प्रतीक है, एक उभरती हुई शक्ति को वैश्विक राजनीति की प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे करनी चाहिए। इस चुनौती के प्रति भारत की प्रतिक्रिया न केवल उसकी ऊर्जा नीति को आकार देगी, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी पहचान को भी निर्धारित करेगी। व्यावहारिकता और सिद्धांत, स्वायत्तता और सहयोग के बीच संतुलन बनाकर भारत यह सिद्ध कर सकता है कि रणनीतिक स्वतंत्रता वैश्विक साझेदारी के लिए बाधा नहीं, बल्कि समानता और सम्मान पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संबंधों की आधारशिला है। रूसी तेल पर भारत का रुख वैचारिक हठधर्मिता नहीं, बल्कि आर्थिक आवश्यकताओं और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का तार्किक मूल्यांकन है। अमेरिका भले ही भविष्य में दबाव बढ़ाता रहे, परंतु भारत की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था के प्रति है। आगे का मार्ग किसी एक पक्ष को चुनने में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता को मजबूत करने में निहित है। वैश्विक रूप से परस्पर जुड़े संसार में स्वतंत्र विकल्प चुनने की क्षमता ही किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होती है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत एक आत्मविश्वासी, संप्रभु और दूरदर्शी राष्ट्र के रूप में उभर सकता है, जो बदलती वैश्विक शक्ति संरचना में अपनी विशिष्ट पहचान और भूमिका स्थापित करने में सक्षम हो।

# ट्रंप के लिये दुश्वार नहीं 'ऑपरेशन - ग्रीनलैंड'

विश्व राजनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के निर्लज्ज और दुस्साहसिक अपहरण तथा अनापशनाप टैरिफ के जरिये अनेक मुल्कों की मुश्कें कसने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हौसले बुलंद हैं और वह किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं। बुधवार को स्विट्जरलैंड में आल्प्स की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्लूईएफ) के सम्मेलन में उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि अमेरिका ग्रीनलैण्ड को लेकर रहेगा, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही उसकी हिफाजत कर सकता है। उन्हें ग्रीनलैंड पट्टे पर नहीं चाहिये, वरन उसका अधिकार, सनद और स्वामित्व भी चाहिये। यदि डेन्मार्क ने 'नहीं' कहा तो वह इसे याद रखेंगे। स्पष्ट है कि ट्रंप उत्तरी गोलार्द्ध में आर्कटिक क्षेत्र में स्थित इस हिमाच्छादित अल्प-स्वायत्त डेनिश भूखंड को बज़िद हासिल करना चाहते हैं और अपना मंसूबा पूरा करने के लिये वह कोई कोर कसर नहीं उठा रखेंगे।

पूरे योरोपीय यूनियन के आधे से अधिक साइज़ का ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा हिमानी द्वीप है। भारत उससे आकार में सिर्फ डेढ़ गुना बड़ा है, लेकिन ग्रीनलैंड की कुल आबादी 57 हजार है। देश का 80 फीसद इलाका 30 लाख वर्ष पूर्व निर्मित बर्फ की चादर से ढँका हुआ है। देश की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी पाँच नगरों में रहती है। राजधानी नुक की आबादी करीब 20 हजार है। सिसिमियुट में 5485, इलुलिसैट की 5087, कार्कोताक की 3069 और आसियात की 2992 है। जाहिर है कि भारत के छोटे-छोटे कस्बों की आबादी भी इनसे ज्यादा है। यहाँ ग्रीष्म में 24 घंटे सूर्य अस्त नहीं होता, वहीं शीत में चौबीसों घंटे सूर्योदय नहीं होता। आर्कटिक रेखा आठ देशों-कनाडा डेन्मार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका (अलास्का) के हिस्सों से होकर गुजरती है। इसका उत्तरी क्षेत्र आर्कटिक कहलाता है। इस सर्कल में बर्फ का पिघलना जलवायु-परिवर्तन के

मान से मानीखेज है। ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर लगातार 29वें साल सिकुड़ी है। ग्रीनलैंड की आइसशीट प्रतिवर्ष 140 बिलियन टन हिम गंवा रही है। अनुमान है कि इससे अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिये नार्थ-वेस्ट पैसेज बनेगा। अमेरिका की दिलचस्पी का यह एक बड़ा कारण है, दूसरे यहाँ 'रेअर अर्थ मिनेरल्स' का विपुल भंडार है। लौह अयस्क के अलावा यहां ग्रेफाइट, टंगस्टन, पैलेडियम, वैनेडियम, जिंक, सोना, यूरेनियम, तांबा और तेल आदि का अपार भंडार मौजूद है। यह भंडार महाशक्तियों के आकर्षण का केन्द्र है। इसी दुर्लभ खजाने के लाभ में चीन ने खुद को 'निकट आर्कटिक राज्य' घोषित कर दिया है, जो अमेरिका के लिये चिंता का सबब है।

जर्मनी से लगभग छह छह गुने बड़े ग्रीनलैंड की रक्षा का दायित्व डेन्मार्क का है, जिसने उसे काफी स्वायत्तता दे रखी है। अमेरिका इसे अपने सामरिक हितों के लिये महत्वपूर्ण मानता है। करीब डेढ़ सौ साल पहले सन् 1867 में अमेरिकी विदेशमंत्री विलियम सेवर्ड ने ग्रीनलैंड के अमेरिका में विलय का मुद्दा उठाया था। दूसरे विश्व युद्ध में इसे जर्मनी के आधिपत्य से बचाने के लिये अमेरिका ने इसके सामरिक भागों पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका फिलवक्त पश्चिमोत्तर में स्थित पिटूफिक स्पेस बेस का संचालन करता है, जो सन 1951 में अमेरिका-डेन्मार्क की संधि से अस्तित्व में आया था। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी धमकी की योरोप में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि न तो कोई धमकी और न ही कोई दबाव हमें प्रभावित करेगा। न उक्राइना में और न ग्रीनलैंड में और न ही कहीं और। यूरोपियन यूनियन (ईयू)-प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लोयेन ने भी कहा कि योरोप अमेरिका की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। डब्ल्यूईएफ की बैठक में जब कनाडा के पीएम कार्नी, जिन्होंने कनाडा को 51वाँ अमेरिकी राज्य बनाने की ट्रंप की दंभोक्ति का विरोध किया था, बोलने को खड़े हुये तो सभी उपस्थित गणमान्यों ने खड़े होकर करतलध्वनि से उनका स्वागत किया। इस गणमान्यों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा, कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स ट्शीसेकेडी, चीन के उपप्रधानमंत्री ही लीफेंग और उक्राइना के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलिंस्की शामिल थे। ट्रंप के अड़ियल रवैये से नाटो में दरार का खतरा उत्पन्न हो गया है। डेन्मार्क के नाटो का सदस्य होने से यदि अमेरिका ग्रीनलैंड में सैन्य कार्रवाई करता है तो नाटो- देशों के सम्मुख सांप-छछुंदर की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। नाटों के सदस्य आठ योरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में गिनेचुने सैनिक तो भेजे हैं, लेकिन आसार यहीं है कि उनकी मौजूदगी वहाँ झड़प का रूप लेगी। बहरहाल, इस घटनाक्रम से रूस और चीन की बांछे खिली हुई हैं, क्योंकि एक तो इससे नाटो की बिरादरी में आशंकाओं और भय को बढ़ावा मिलेगा, दूसरे उक्राइना पर रूस और ताइवान पर चीन के आधिपत्य के दावों को वैधता और ताकत मिलेगी।

ट्रंप के तल्ख तेवरों का पता इससे चलता है कि वह ग्रीनलैंड को बर्फ का छोटा, ठंडा और दुर्गम टुकड़ा बताते हुये कहते हैं कि डेन्मार्क अहसान फरामोश है। अमेरिका ने बीते दशकों में उसे जितना दिया है, उसके मुकाबले यह मांग तुच्छ है। उन्होंने कहा कि- 'मैं योरोप से प्रेम करता हूँ और उसका भला चाहता हूं, लेकिन वह सही दिशा में नहीं जा रहा है।' बहरहाल, अब सबकी निगाहें डेन्मार्क के विदेशमंत्री लार्स लोके रासमुसेन की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेशमंत्री रूबियो से वाशिंगटन में प्रस्तावित वार्ता पर हैं, लेकिन ट्रंप की ज़िद और सनक के चलते कोई नतीजा निकलने की संभावना नगण्य है। इस बीच अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की ने न्यू हैंपशायर की डेमाक्रेट-साथी जीन शाहीन के साथ सीनेट में एक बिल पेश किया है, जिसका मकसद किसी दूसरे नाटो सदस्य के इलाके पर एकतरफा कब्जे पर रोक लगाना है।

# पेड़ों को बचाने के लिए कोयंबटूर की मिसाल

पर्यावरण

संदीप कुलश्रेष्ठ

सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा निर्माण कार्य किया जाता है तो पेड़ों की बलि चढ़ जाती है। यानी जहां भी विकास होता है, वहां हरियाली नष्ट कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में तमिलनाडू के कोयंबटूर ने देश के सामने मिसाल कायम की है। यहां सड़क चौड़ीकरण, हाईवे निर्माण या विकास की किसी दूसरी परियोजना के लिए पेड़ नहीं काटे जाते, बल्कि तय यह किया जाता है कि कौन-कौन से पेड़ बचाए जा सकते हैं। करीब एक दशक से बड़े पेड़ कटाने का दर्द झेल चुका कोयंबटूर अब देश के लिए एक मिसाल बन गया है। यहां पिछले करीब 10 साल में 5 हजार से ज्यादा पेड़ एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाए गए। इन नई जगह लगाए गए पेड़ों के बचने का प्रतिशत 85 प्रतिशत है। ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्य है। जिला प्रशासन, वन विभाग, एनएचएआई और पर्यावरणीय संगठनों ने मिलकर कोयंबटूर में पेड़ नहीं काटने का एक आदर्श मॉडल विकसित कर दिखाया है।

कोयंबटूर में जब कोई निर्माण परियोजना शुरू हो रही होती है, जिसमें पेड़ों को काटने की जरूरत होती है, तब सबसे पहले स्वस्थ्य पेड़ों की पहचान की जाती है। इन पेड़ों की जड़ों की मिट्टी साथ में सुरक्षित की जाती है। शाखाए छांटी जाती है, ताकि किसी पेड़ पर तनाव न पड़े। सरकारी क्रेन और मशीनों से पूरा पेड़ एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रोपित किया जाता है। विशेषकर स्कूल, पार्क, मंदिर परिसर या किसी ग्रीन बफर जोन में उसे दोबारा लगाया जाता है। शुरूआत के करीब 3 महीने ऐसे पेड़ों पर विशेष निगरानी रखी जाती है और नियमित रूप से सिंचाई भी की जाती है। इसके बाद पेड़ नई जगह के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं।

करीब 10 साल पहले कोयंबटूर शहर के लोगों को तब झटका लगा, जब सड़क चौड़ीकरण कार्य में 7,600 पेड़ काट दिए गए। इसके बाद शहरी के लोग अपने शहर की हरियाली बचाने के लिए एक साथ आगे आए। लोगों ने यह तय किया कि विकास तो होगा, किन्तु पेड़ नहीं काटे जायेंगे। लोग जागे तो सरकारी मशीनरी भी जागी, एनजीओ भी आगे आए। पिछले साल ही एक अविनाशी-मेट्टुपालयम मार्ग पर 262 पेड़ बचाए गए। अब लोगों ने यह नियम भी बना लिया है कि हर कटने वाले पेड़ के बदले 10 पौधे लगाना हैं, और वे लगा भी रहे हैं।

कोयंबटूर ने जो अभिनव नई पहल आरंभ की है, उससे देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए इंदौर में नए बायपास रिंगरोड के लिए 5,176 पेड़ काटे जायेंगे। ऐसी स्थिति में इंदौर को कोयंबटूर से प्रेरणा लेकर अपने यहां भी सभी पेड़ों को बचाने की पहल करना चाहिए। इसी तरह उज्जैन में आगामी सिंहस्थ के लिए व्यापक रूप से निर्माण कार्य और रोड चौड़ीकरण हो रहे है। इसमें भी पेड़ों की बलि दी जा रही है। उज्जैन को भी कोयंबटूर से प्रेरणा लेकर अपने यहां के भी पेड़ को बचाना चाहिए। इसी प्रकार देश के अन्य शहरों को भी कोयंबटूर से प्रेरणा लेकर नए निर्माण के लिए पेड़ों की बलि पर सख्ती से रोक लगाना चाहिए। यह काम अकेले सरकार का नहीं है। इसलिए लोगों को भी आगे आना जरूरी है और उन्हें पर्यावरण बचाने के लिए यह काम करना ही होगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

**प्रधान संपादक**
उमेश त्रिवेदी
**कार्यकारी प्रधान संपादक**
अजय बोकिल
**संपादक (मध्यप्रदेश)**
विनोद तिवारी
**स्थानीय संपादक**
हेमंत पाल
**प्रबंध संपादक**
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

**'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।**

# सुन बेटा सुन, ई पुतले में बड़े- बड़े गुन !

व्यंग्य

सुधीर नायक
(व्यंग्यकार)

मुझे आजतक समझ में नहीं आया कि पुलिस का पुतले से कौन-सा याराना है? वह पुतले को जलाने क्यों नहीं देती? पुलिस क्यों बीच में पड़ती है? दिक्कत क्या है? जल जायेगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। अरे भाई वे पुतला ही तो जला रहे हैं किसी का दिल तो नहीं जला रहे हैं। दिल जलाने से तो अच्छा है पुतला जलाना। यहां तो वर्षों से दिल जल रहा है उसकी तो पुलिस को परवाह नहीं है। पुतलों के पीछे पड़ी है। बात को समझा करे, अभी मामला पुतले में ही निपट रहा है। पहली फुरसत में निपटा लेना चाहिए। पुलिस वाले फालतू चक्कर में पड़ते हैं। वैसे भी,आजकल के पुतलों में दम नहीं रही। बहुत फुस्सी टाइप के पुतले आ रहे हैं।दो मिनट नहीं लगेंगे जलने में। पहले जैसा नहीं है कि पुतले धूं धूं करके घंटों जलते थे।और मैं सच बताऊं,पुलिस छीनती है इस चक्कर में ज्यादा पुतले जलते हैं।पुलिस झूमा झटकी बंद कर दे तो आधे से ज्यादा पुतले कम हो जायेंगे। रील बनाने का मजा छीना-झपटी में ही है। पुलिस न छीने तो बहुत सारे पुतले अनजले रह जायेंगे। मालूम है आपको? आजकल लोग माचिस नहीं ले जाते। उन्हें मालूम है पुलिस छीन ही लेगी। और जो कुछ लोग माचिस ले भी जाते हैं वे माचिस से पुतला नहीं सुलगाते,बीड़ी सुलगाते हैं। वे बीड़ी फूंकते हुए इंतजार करते हैं कि पुलिस आये और पुतला छीने। पुलिस की गाड़ी आती है तब माचिस की काड़ी निकलती है। पुलिस को नहीं पता कि वह पुतला छीनकर कितने अरमानों पर पानी फेर देती है।

कितने सारे अभागे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका एकाध पुतला जल जाये। पुतले जलाने वाले बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं। वे भी देख परख कर जलाते हैं। उन्हें भी अपना फ्यूचर देखना है। हर किसी का थोड़े ही जला देंगे। दरअसल नेता का पुतले से खट्टा मीठा रिश्ता है।नेता जब छोटा होता है तब चाहता है कि उसका पुतला जल जाये और वही नेता जब बड़ा हो जाता है तो चाहता है कि अब पुतला न जले। पुतले की बड़ी माया है। छोटे नेता को चमकाता है,बड़े नेता को धमकाता है। अब समय आ गया है जब लोगों को अपना पुतला खुद जलाने की छूट दे दी जानी चाहिए। मौका अच्छा है। आत्मनिर्भर भारत की धूम मची हुई है। इसी हल्ले में पुतला जलाने में भी आत्मनिर्भर हो भगें तो अच्छा है। पुतला जलाने वालों के नखरे कम होंगे। इसी प्रश्न से और भी प्रश्न निकलते हैं कि आखिर लोग पुतला ही क्यों जलाते हैं? कुछ और जला लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जलाने को। और फिर जलाते ही क्यों हैं? जमीन में गाड़ दें,नोंच लें,खसोट लें,पटक दें,कुचल दें,रौंद डालें। जहां तक मेरी जानकारी है पुतला केवल भारत में ही जलता है। हम इसकी मार्केटिंग क्यों नहीं करते? कम से कम इस मामले में तो हम विश्वगुरु बने बनाये हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि अमेरिका, इंग्लैंड में कोई पुतला जलाया गया हो। वहां की पुलिस फुर्सत बैठी रहती है। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि पुतला दहन की शुरुआत कैसे हुई होगी? पहला पुतला किसने जलाया होगा? यह पता चल जाये तो हम पुतला दहन दिवस की शुभकामनाएं दें उस दिन की छुट्टी की मांग उठायें। मुझे लगता है कि पुतले का कांसेप्ट शायद तंत्र मंत्र से आया होगा।लोग दुश्मन का पुतला बनाकर उस पर तंत्र मंत्र करवाते थे। पुतला दहन शायद उसी का अवशेष है। लेकिन अब उसमें दूसरे का अहित करने के बजाय अपना हित साधने का भाव ज्यादा आ गया है। यह शुभ लक्षण है। पुतला अब साधु स्वभाव का हो गया है। पुतला खुद जलकर भी जलाने वालों को चमका जाता है। कई लोग हैं जो पुतले जला जलाकर ही उठ गये। भगवान की कृपा है आज उनके खुद के पुतले जलते हैं। फिर भी पुतला जलाने वाले हमारी प्राचीन तांत्रिक परंपरा की यादें सहेजे हुए हैं। उनका सम्मान होना ही चाहिए। खैर जो भी हो,हम तो जीवन भर ललकते रहे। हमारा तो किसी ने पुतला क्या एक छोटी सी पुतली भी नहीं जलायी।

विश्व रेडियो दिवस

प्रो. मनोज कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया शिक्षा से संबद्ध हैं

# मेरी आवाज़ ही पहचान है

***रेडियो एक नए अनुभव की तरह हमारे साथ-साथ चल रहा है. किसी समय रेडियो के लिए लायसेंस लेना होता था तो आज टेक्नालॉजी ने सारे मायने बदल दिए हैं और हथेलियों पर बंद मोबाइल फोन में आप अपना पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम, गीत-संगीत सुन सकते हैं. हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो इसके पीछे भी ठोस कारण है और वह है कि इस दिन 13 फरवरी, 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी. संयुक्त राष्ट्र के रेडियो लोकतांत्रिक संवाद का सर्वोत्कृष्ट मंच मानता है. पहली रेडियो सेवा 23 फरवरी 1920 को और पहली खेल रेडियो रिपोर्ट 11 अप्रैल 1921 को प्रसारित हुई थी तब से रेडियो युवा और गतिशील बना हुआ है. भारत में ऑल इंडिया रेडियो का नाम एकजाई कर आकाशवाणी कर दिया गया है.***

सड़क से सरकार तक संचार के माध्यमों में अपने जन्म से लेकर अब तक भरोसेमंद साथी रेडियो रहा है. भारत की आजादी की ख़बर हो या दैनंदिनी गतिविधियों की पुख्ता और सही जानकारी रेडियो से ही मिल पाती है. एक समय हुआ करता था जब रेडियो का मतलब आकाशवाणी हुआ करता था लेकिन अब शहरी इलाकों में एफएम और गाँव-खेड़े के लिए सामुदायिक रेडियो प्रचलन में है. रेडियो एक नए अनुभव की तरह हमारे साथ-साथ चल रहा है. किसी समय रेडियो के लिए लायसेंस लेना होता था तो आज टेक्नालॉजी ने सारे मायने बदल दिए हैं और हथेलियों पर बंद मोबाइल फोन में आप अपना पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम, गीत-संगीत सुन सकते हैं. हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो इसके पीछे भी ठोस कारण है और वह है कि इस दिन 13 फरवरी, 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी. संयुक्त राष्ट्र के रेडियो लोकतांत्रिक संवाद का सर्वोत्कृष्ट मंच मानता है. पहली रेडियो सेवा 23 फरवरी 1920 को और पहली खेल रेडियो रिपोर्ट 11 अप्रैल 1921 को प्रसारित हुई थी तब से रेडियो युवा और गतिशील बना हुआ है. भारत में ऑल इंडिया रेडियो का नाम एकजाई कर आकाशवाणी कर दिया गया है.

अमीन सयानी और रेडियो सीलोन एक-दूसरे के पर्याय माने जाते हैं. दुनिया के सबसे पुराने रेडियो प्रसारकों में से एक, रेडियो सीलोन ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए. ऐसे समय में जब रेडियो एक नई चीज थी और टीवी द्वारा दक्षिण एशिया के मीडिया परिदृश्य को बदलने से दशकों पहले, रेडियो सीलोन ने आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर, 1925 से प्रसारण शुरू किया. यह एशिया का पहला रेडियो प्रसारक था. भारत में निजी रेडियो प्रसारण 1927 में शुरू हुआ, जबकि ऑल इंडिया रेडियो ने 1936 में परिचालन शुरू किया. नीदरलैंड 1919 में सार्वजनिक प्रसारण शुरू करने वाला पहला देश था, जिसके बाद 1920 में अमेरिका ने इसका अनुसरण किया.

आमतौर पर बोलचाल में हम एक संबोधन रेडियो कह देते हैं लेकिन रेडियो और ट्रांजिस्टर में बुनियादी फर्क है. रेडियो एक स्थूल उपकरण है जबकि ट्रांजिस्टर मोबाइल की तरह चलायमान. 1947 में डब्ल्यू. शॉकली के नेतृत्व में बेल लेबोरेटरीज (यूएसए) में ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने वाल्व वाले रेडियो का अंत कर दिया. 1954 में, अमेरिकी कंपनी रीजेंसी ने पहला पूरी तरह से ट्रांजिस्टर वाला रेडियो बनाया और बेचा. हालाँकि अब इसे पीसी या स्मार्टफोन से भी सुना जा सकता है, लेकिन फर्नीचर के रूप में रेडियो का आकर्षण आज भी बरकरार है और समय के साथ इसमें ऐसी तकनीक और कार्यक्षमता जुड़ती गई है जो पहले मौजूद नहीं थी.

रेडियो तकनीक की चर्चा करें तो अब हम विजुअल रेडियो की दुनिया में पहुँच गए हैं. कानों सुनी के साथ अब आँखों देखी रेडियो का जमाना भी आ गया है, इसे विजुअल रेडियो का नाम दिया गया है. विजुअल रेडियो में एक आधुनिक प्रसारण तकनीक है जो पारंपरिक रेडियो की ऑडियो सामग्री को दृश्य तत्वों (विजुअल्स) के साथ जोड़ती है. इसमें रेडियो प्रसारण के साथ-साथ चित्र, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री को एकीकृत किया जाता है, जिसे श्रोता रेडियो सेट, मोबाइल ऐप या इंटरनेट के माध्यम से सुनने के साथ साथ रेडियो प्रसारण को देख भी सकते हैं. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात से भी समझ सकते हैं. मन की बात मूलतः रेडियो पर प्रसारित एक ऑडियो कार्यक्रम है लेकिन रेडियो प्लस यानि रेडियो सेट से इतर जब इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें दृश्य भी जोड़ दिए जाते हैं.

सड़क से सरकार तक रेडियो की उपयोगिता बनी हुई है. खेत में जाता किसान, मजदूरी के लिए जाता मजदूर अपने कंधे पर ट्रांजिस्टर सेट लटका कर सुनते हुए चलता हुआ कहीं भी दिख जाता है. अब नए जमाने में कार में रेडियो ट्यून कर लेते हैं या मोबाइल पर भी ट्यून कर पसंदीदा गीत सुन सकते हैं. इस दौर में सामुदायिक रेडियो का आगमन हुआ और यह दूर-दराज इलाके जहाँ संचार की सुविधा नहीं है, उनके लिए वरदान साबित हुआ. औसतन पंद्रह किलोमीटर रेंज में प्रसारित होने वाले सामुदायिक रेडियो समुदाय विशेष के लिए होता है. खास बात यह है कि इस रेडियो का संचालन भी समुदाय विशेष के लिए किया जाता है. महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो के प्रभाव को समझा और लोगों से सीधा संवाद करने के लिए उसे चुना. 'मन की बात' कार्यक्रम से ना केवल आकाशवाणी को आर्थिक लाभ हुआ अपितु देश भर की छिपी प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिला. कम खर्च, सीमित संसाधन लेकिन एक सौ तीस करोड़ लोगों से संवाद का यह अनूठा प्रयास प्रभावकारी हुआ है.

मध्यप्रदेश के संदर्भ में रेडियो की बात करना सुखद लगता है. जनजातीय विभाग ने आदिवासी बहुल इलाकों में रेडियो प्रसारण के जरिए जनजातीय समुदाय में जागृति लाने एवं मुख्यधारा से जोड़ने का अथक प्रयास किया. वर्ष 2010 में कम्युनिटी रेडियो स्थापना की कार्यवाही आरंभ की गई और 2012 आते-आते आठ कम्युनिटी रेडियो आदिवासी अंचलों में बजने लगे थे. नाम दिया गया 'रेडियो वन्या'. 'रेडियो वन्या' के स्टेट कॉर्डिनेटर के नाते अनुभव का एक नया संसार रचने का अवसर मिला. ये सभी रेडियो स्टेशन आदिवासी बोलियों में प्रसारित हो रहे थे. चुनौती थी कि बोलियों में प्रामाणिकता एवं शुद्धता की थी सो आदिवासी बोलियों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर हिन्दी में मेरे बनायी गई स्क्रिप्ट को वे बोलियों में बदल देते थे. इस तरह सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदाय को मिलने लगा. इसके साथ ही तब के संस्कृति संचालक श्रीराम तिवारी के प्रयासों से देश का एकमात्र स्वाधीनता संग्राम पर एकाग्र कम्युनिटी रेडियो 'रेडियो आजाद हिन्द' का प्रसारण होने लगा. इस अनुभव के साथ मुझे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो स्थापना के लिए पहले सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी दी गई. तत्कालीन कुलपति प्रो. के.जी. सुरेश के साथ 'रेडियो कर्मवीर' का प्रसारण आरंभ हो गया. इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित डॉ. रामामूर्ति भी 'रेडियो कर्मवीर' की सलाह ली गई थी. इन अनुभवों को एकाग्र कर कम्युनिटी रेडियो पर हिन्दी में पहली किताब कही जा सकती है. कहा जा सकता है कि कम्युनिटी रेडियो के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की अलग ही पहचान है. आदिवासी बोलियों में रेडियो प्रसारण वाला मध्यप्रदेश संभवतः अपनी तरह का इकलौता प्रदेश है.

रेडियो का असीमित और स्थायी प्रभाव आज भी बना हुआ है या यों कह सकते हैं कि समय के साथ रेडियो की उपयोगिता में श्रीवृद्धि हुई है. रजतपट और रेडियो का चोली-दामन का साथ रहा है. अनेक नई-पुरानी फिल्मों में रेडियो को प्रभावी माध्यम के रूप में देखा और समझा गया है. हालिया फिल्म 'मेरी सुलु' ने जता दिया कि रेडियो जॉकी के लिए खांटी प्रोफेशनल्स होना जरूरी नहीं, बस इस मीडिया के लिए जुनून और जज्बा चाहिए. कहना पड़ेगा मन का रेडियो बजने दे जरा...

विश्व रेडियो दिवस

डॉ. ललित कुमार

लेखक इन्वर्टिस विश्व विद्यालय बरेली में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष हैं।

# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए सशक्त माध्यम बना रेडियो

**विश्व रेडियो दिवस के रूप में 13 फरवरी का दिन वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र में रेडियो की स्थापना की स्मृति के रूप में जाना जाता है। रेडियो अपने आप में एक अनोखा और आकर्षण का केंद्र रहा है, जो अपनी आवाज से श्रोताओं को बांधकर रखता है। वर्ष 1916 में रेडियो के ज़रिए पहली बार समाचार प्रसारित किया गया। यह समाचार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सूचना से जुड़ा था। प्रिंट मीडिया से कुछ घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लोग रेडियो के ज़रिए सूचना पाकर इतना खुश हुए कि उन्होंने इसे अपनाने में जरा भी देर नहीं लगाई और अमेरिका में पहली बार लोगों को लगा कि रेडियो को संचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडियो सामूहिक श्रवण का माध्यम होने के साथ-साथ लोगों को न केवल आपस में जोड़ने का माध्यम बना बल्कि अपने अनुभव को साझा करने का भी माध्यम बना।**

रेडियो माध्यम दुनिया में जनसंचार का एक ऐसा माध्यम रहा है, जिसने अपने ऊपर कभी कोई आंच नहीं आने दी। आम जनता की आवाज के रूप में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने वाला यह माध्यम हमेशा हर काल खंड में लोगों के दिल दिमाग पर राज करता आया है। रेडियो को सबसे शालीन और सबसे सस्ता माध्यम इसलिए भी कहा जाता है। क्योंकि इस माध्यम ने कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। वेब तरंगों के रूप में लोगों को सूचना देने वाला यह माध्यम हर वर्ग का सबसे भरोसेमंद माध्यम कहा जाता है।

विश्व रेडियो दिवस के रूप में 13 फरवरी का दिन वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र में रेडियो की स्थापना की स्मृति के रूप में जाना जाता है। रेडियो अपने आप में एक अनोखा और आकर्षण का केंद्र रहा है, जो अपनी आवाज से श्रोताओं को बांधकर रखता है।

वर्ष 1916 में रेडियो के ज़रिए पहली बार समाचार प्रसारित किया गया। यह समाचार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सूचना से जुड़ा था। प्रिंट मीडिया से कुछ घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लोग रेडियो के ज़रिए सूचना पाकर इतना खुश हुए कि उन्होंने इसे अपनाने में जरा भी देर नहीं लगाई और अमेरिका में पहली बार लोगों को लगा कि रेडियो को संचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडियो सामूहिक श्रवण का माध्यम होने के साथ-साथ लोगों को न केवल आपस में जोड़ने का माध्यम बना बल्कि अपने अनुभव को साझा करने का भी माध्यम बना।

विश्व रेडियो दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र, शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक, संगठन यानी यूनेस्को ने वर्ष 2011 के अपने 36वें आम सम्मेलन में की थी। जबकि वर्ष 2012 में 67वें सत्र में इसे अपना लिया गया था रेडियो ऐसी विपरीत परिस्थितियों से गुजरने वाला माध्यम रहा, जिसने अपने श्रोताओं को बहुत ही सरल एवं सहज़ तरीके से सूचना पहुंचाने का काम किया है। यही कारण रहा है कि रेडियो अपनी सरल विधा के रूप में श्रोताओं के बीच एक नहीं पहचान बनाने वाला माध्यम बना। रेडियो ने 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी के ऐतिहासिक रूप में जनता को सूचना पहुंचाने में एक विशाल भूमिका निभाई।

वर्ष 2026 में विश्व रेडियो दिवस पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का आकाशवाणी केंद्र NESCO की मदद से बेबीलॉन कैपिटल होटल में विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष की थीम है 'रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' जहां इस बात पर जोर देने की कोशिश होगी कि तकनीकी के इस दौर में रेडियो अपने मूल प्रसारण के जरिए ध्वनि, संगीत और मूल लेखन को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद से श्रोताओं तक अपनी पहुंच को कैसे मजबूत कर सकता है?

विश्व रेडियो दिवस के अवसर रेडियो का मुख्य उद्देश्य प्रसारकों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, साथ ही सूचना की सफलता और अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना, आम जनता और मीडिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, निष्पक्ष एवं बहुलतावादी रेडियो को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

भारत में कम्युनिटी रेडियो प्रसारण का तीसरा स्तर माना जाता है, जो सार्वजनिक सेवा और कमर्शियल रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो सीमित क्षेत्र के श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने का काम करता है। वर्ष 2004 में 1 फरवरी को देश का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोला गया। इसके बाद वर्ष 2005 में अन्ना यूनिवर्सिटी ने अन्ना कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज की शुरुआत की। इसके बाद से देश के अलग-अलग हिस्सों में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई। कम्युनिटी रेडियो क्षेत्रीय श्रोताओं की आवाज को एक नया मंच प्रदान करता है, जो स्थानीय कलाकारों, लोक परंपरा एवं लोक संगीत की विरासत को संजोने का काम करता है।

वर्तमान भारत में लगभग 528 सामुदायिक रेडियो चलाए जा रहे हैं। सामुदायिक रेडियो का कॉन्सेप्ट अब भारतीय सेना को भी लुभा रहा है। जून 2025 में उत्तराखंड के ज्योर्तिमठ में इबेक्स ताराना 88.4 एमएम कम्युनिटी रेडियो स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य एवं आपदा से जुड़ी सूचनाएं प्रसारित करता है। इसी के साथ जनवरी 2026 में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 'रेडियो संगम' 88.8 एफएम की शुरुआत की। यह सामुदायिक रेडियो नियंत्रण रेखा के पार पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जो देश की दुष्प्रचार से जुड़ी सूचनाओं का मुकाबला करने में एक बेहतर माध्यम माना जा सकता है। यानी डिजिटल प्लेटफार्म व सोशल मीडिया के साथ-साथ रेडियो ने अपनी एक नयी रफ्तार पकड़ी है।

3 अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए रेडियो को एक नई पहचान दी जिसके अब तक 130 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष रेडियो एक नए सिरे से अपनी पहचान को मजबूती के साथ श्रोताओं को सूचना देने का काम कर रहा है। यानी डिजिटल युग में रेडियो एक नई तरीके से आम जनता तक पहुंच रहा है, जो लोगों को मनोरंजन एवं जागरूकता के साथ तथ्यपरक सूचना देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में लगा है।

विचार

सीमा देवेन्द्र

लेखक साहित्यकार हैं।

# प्रेम में आत्महत्या नहीं आत्मसमर्पण करें

**प्रेम करने की न तो कोई ऋतु होती है और न ही कोई सप्ताह, पखवाड़ा, दिन या महिना होता। ये तो स्वतः ही होता है और बस हो जाता है। हां ये हर किसी से होता रहे कुछ कुछ महिनों में तो निश्चित ही फिर वो प्रेम तो कतई हो ही नही सकता। फिर वो टाइम पास वाला मजा मस्ती है जिसे फ़ितरत भी कहा जा सकता है और फितरत फुर्सत की ही उपज है। प्रेम एक घटना है जिसमें व्यक्ति अपने आप से कहीं दूर निकल जाता है जहां से लौट पाना मुश्किल नही बहुत ही मुश्किल, असम्भव सा होता है। बसंत तो आता जाता रहता है लेकिन प्रेम बसंत क्षणिक नही होता ये जीवन में जब आता है फिर लौटता नही है। इसका एक अलग ही मधुर संगीत होता है जो बांधे रखता है लय से लय को प्रकृति को।**

प्रेम में भटकाव हो तो ध्यान करें और लगाव हो तो निदान करें! गुमराह होना और ट्रेक बदलना अलग अलग स्थित का पता देती है। जिसके परिणाम आए दिन अखबारों में दिखाई दे रहे हैं। ये नादान की दोस्ती और जी का जंजाल हो सकता है, लेकिन पढ़े लिखे परिपक्व का हर कदम सोंचा समझा होता है। प्रेम जीना चाहता है इसमें आत्महत्या क्यों करनी है ? यह तो हृदय से हृदय का मौन संवाद है। इसमें वादे हैं ईरादे हैं... तो ठीक है ना, वो भी तो जीवन के मैनेजमेंट का हिस्सा है ! क्योंकि प्रेम जब हुआ था परिस्थितियाँ तो तब भी वही थी जो वर्तमान में होंगी। इसलिए प्रेम की लड़ाई में हार कैसी ? जीत तो प्रेम की ही होना है। सच्चा प्रेम कभी हारा नही, ये बसंत वसंत कुछ नही देखता।

प्रेम करने की न तो कोई ऋतु होती है और न ही कोई सप्ताह, पखवाड़ा, दिन या महिना होता। ये तो स्वतः ही होता है और बस हो जाता है। हां ये हर किसी से होता रहे कुछ कुछ महिनों में तो निश्चित ही फिर वो प्रेम तो कतई हो ही नही सकता। फिर वो टाइम पास वाला मजा मस्ती है जिसे फ़ितरत भी कहा जा सकता है और फितरत फुर्सत की ही उपज है। प्रेम एक घटना है जिसमें व्यक्ति अपने आप से कहीं दूर निकल जाता है जहां से लौट पाना मुश्किल नही बहुत ही मुश्किल, असम्भव सा होता है।

बसंत तो आता जाता रहता है लेकिन प्रेम बसंत क्षणिक नहीं होता ये जीवन में जब आता है फिर लौटता नहीं है। इसका एक अलग ही मधुर संगीत होता है जो बांधे रखता है लय से लय को पृकृति को।

प्रेम प्रकृति है, जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यदि हम प्रकृति से भी प्रेम करते हैं तो वो भी हमें कई गुना वापस लौटाती है। ठीक वही गुण प्रेम का होता है। ईमानदारी से किया गया प्रेम भी कई गुना होकर वापस लौटता है। जिसका कोई तोल मोल नहीं है उसे तो बस महसूस किया जा सकता है।

प्रेम मानवीय गुण है। ये किसी उत्सव का मोहताज नही होता। जो हर पल प्रेम में जी रहा है वह तो सदैव अपने को चारों ओर बसंत से घिरा हुआ महसूस करता है।

अभी देखने में आ रहा है प्रेम में प्रॉमिस डे होता है जिसमें हर वर्ष प्रॉमिस करना होता है। अब इसमें कितने ग्राम का भरोसे वाला प्रॉमिस होता है और ये कब तक चलेगा इसकी एक्सपायरी डेट कब तक की होती है ? देखने की बात ये है। इसमें दो बात होती है - एक तो नादान लोग समझ नही पाते और दूसरे चालाक लोग समझने नही देते।

इसलिए हमारे यहां प्रॉमिस नहीं, वादे होते हैं, संकल्प होते हैं जो जन्म-जन्मान्तर के होते हैं। वो फिर कोई भी रिश्ता हो, बात ज़ुबान से ज़ुबान की होती है। 'प्राण जाई पर वचन न जाई'।

ये राम का देश है, सीता सावित्री का देश है।

विश्वास,भरोसे, सम्मान और समर्पण का नाम ही प्रेम है। जिसकी अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं तय है। पवित्र प्रेम में चालाकी और बेईमानी की जगह नहीं होती।

पाश्चात्य अंधानुकरण और आधुनिकता वाला ये प्रेम दिवस और प्रपोज दिवस अत्यंत घातक है जिसकी एक्सपायरी डेट पहले से तय है।

हर चार-छः महिने मे नए चुनाव हो जाना और बहाने में समाज और परिस्थितियों का रोना रोया जाता है। जबकि समाज और परिस्थितियाँ तो पहले भी वही होती है और वर्तमान में भी। फिर क्या सोंच कर किस बुद्धिमानी से प्यार का नाटक रचा जाता है, के बाद में समाज स्वीकार्यता आड़े आ जाती है। इसमें ये बात तय है कि प्रेम बुद्धिमान लोग नही किया करते वे तो बस बुद्धिमानी की बात किया करते हैं। ये प्रेम का उपहास है जो चैट से शुरू होकर चैट डिलीट के विवाद पर खत्म हो जाता है।

धड़ल्ले से चल रही आज इस विचार धारा को समझने की अति आवश्यकता है। जानते हुए भी एकनिष्ठ न होना ये कदम चरित्र और नैतिक पतन की ओर इंगित करते हैं। अपने सुकून और ऐन्जॉय के लिए युवाओं में भटकाव और मतिभ्रम की स्थिति ही ऐसे दिवस को बढ़ावा दे रही है। पाक मुहब्बत की अहमियत समझें ये पाक रिश्तों, फरिश्तों की ज़मी है। यहां प्रेम को भगवान समझा जाता है। प्रेम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करें। भरोसे के महल बनाइए हवाई महल नही।

प्रेम हृदय का अविरल प्रवाह है,छल छद्म से दूर। प्रेम को एक दिन नहीं, हर दिन हर पल जिएं। प्रेम है तो वसंत है। यदि प्रेम नही है तो वसंत में खिलते पीले फूल, नीले आकाश में इन्द्रधनुषी रंग, सुगंधित हवाएं, मदमाता पलाश, वृक्षों और लताओं का आलिंगन इन सबका कोई मतलब ही नही रह जाता। वसंत को प्रेम की निगाहें ही देख सकती है और फागुन को प्रेमी हृदय ही महसूस कर सकता है, बस वही कामयाब वसंत है।

प्रेम जीवन देता है। प्रेम व्यक्तिगत मानसिक विकास की अवधारणा है। प्रेम में आत्महत्या करना पड़े वो प्रेम नही है। अतः प्रेम में आत्महत्या नही आत्मसमर्पण करिए! 'ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन'।

# म.प्र. राज्य मिलेट्स मिशन योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कृषि मेले का शुभारम्भ विधायक नीना विक्रम वर्मा ने किया

**धार।** किसान कल्याण तथा कृषि विकास धार जिला धार के तत्वाधान में तीन दिवसीय कृषि मेले का आयोजन उदय रंजन क्लब में किया गया। कृषि मेले में मुख्य अतिथि नीना वर्मा विधायक धार की उपस्थिति में शुभारम्भ किया गया।कृषि मेले में विधायक द्वारा बताया की जिस प्रकार पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग किसान भाई परम्परागत अनाज कोदो-कुटकी, रागी, सांवा, ज्वार, बाजरा की खेती भी करते थे एवं वही अनाज खाने में भी उपयोग करते थे इसलिए गम्भीर बिमारिया नहीं होती थी। अब इस आधुनिक समय में परम्परागत अनाज को छोडकर गेहू, सोयाबीन की लगातार खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है किसानों अब परंपरागत कृषि की ओर ध्यान देना है शासन द्वारा किसानों के हित में मिलेट मिशन योजना शुरू की है जिसका लाभ लेकर मिलेट श्रीअन्न की खेती करना शुरू करे। वर्तमान में गेहू फसल की कटाई के बाद किसानों भाईयों द्वारा शेष नरवाई को जला दिया जाता है इससे पर्यावरण प्रदुषण एवं मिट्टी के पौषक तत्व नष्ट हो रहे है। किसानों को नरवाई नहीं जलाने की शपथ दिलाई।

कृषि मेले मे अशोक डावर सभापति कृषि स्थाई समिति जिला पंचायत द्वारा मिलेट फसल को कम से कम अपने भोजन में शामिल करने एवं खेती करने के बारे में कहा गया। उप संचालक कृषि ज्ञानसिंह मोहनिया द्वारा बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 11 जनवरी से कृषक

कल्याण वर्ष 2026 मनाया जा रहा है।

मेले में जिले के किसानों भाईयों को वैज्ञानिक एवं विभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिले में मिलेट्स फसलों का रकबा क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने पर जोर दिया जावेगा। मेले के तकनीकी सत्र में कृषि वैज्ञानिक डॉ. अमृतलाल बसेडिया एवं डॉ. नरेश गुप्ता द्वारा मिलेट उत्पादन तकनीकी जानकारी, प्रसंस्करण, मुल्य संवर्धन, विपणन, उन्नत बीज, मृदा परीक्षण, प्राकृतिक एवं जैविक खेती की जानकारी दी गई।

एन. के. ताम्बे सेवानिवृत्त वरिष्ठ कृषि सस्य वैज्ञानिक द्वारा जैविक खाद तैयार करने की विधि, दलहन उत्पादन को बढावा देने और मिलेट फसल कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा का रकबा कम से कम एक एकड़ में लगाने एवं प्राकृतिक तरिके से कीट नियंत्रण की जानकारी कृषकों को दी गई। कृषकों द्वारा लिये गये ज्ञान के आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर कृषकों द्वारा दिया गया जिन्हे पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कोरोमंडल कम्पनी के प्रदर्शिनी स्टॉल में कृषि मेले में नैनो डीएपी के लक्की ड्रॉ में अशोक भारमल ने जीता।

आरएमपीसीएल कम्पनी के लक्की ड्रॉ में सूरजसिंह जामसिंह ग्राम भिलखेडी वि.ख. सरदारपुर को भी उपहार प्रदान किया गया। कृषि मेले में फार्मटेक कम्पनी द्वारा लगाई गयी प्रदर्शिनी से कृषक प्रताप रघुवंशी एवं इरफान पटेल ग्राम बांग्ला बिल्लोद विकाखण्ड नालछा द्वारा ट्रेक्टर खरीदा गया। जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा ब्रजेन्द्र सिंह द्वारा मेले में उपस्थित कृषको को कृषि वैज्ञानिक द्वारा बतायी जा रही फसलो की उन्नत तकनीक को अपनाकर फसलो के उत्पादन बढाने संबंधित जानकारी को अमल करने के संबंध में बताया गया। इसी प्रकार रतनलाल पाटीदार जिला महामंत्री किसान मोर्चा द्वारा कृषकों को मिलेट क्यों जरूरी है, इसके लिए मेले में कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त करने की बात कही।

**इंदौर संभाग में निवेश की बहार**

# पी.एम. मित्रा पार्क के द्वितीय चरण में 7,500 करोड़ रुपये का निवेश

### अब तक निवेश 21,500 करोड़ रुपये के पार, 55 हजार से अधिक रोजगार के अवसर

**धार।** पिछले दो माह में इंदौर संभाग ने निवेश के क्षेत्र में एक बार फिर नए आयाम स्थापित किए हैं। पी.एम. मित्रा पार्क के द्वितीय चरण के आवंटन में कुल 13 कंपनियों को 320 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इन कंपनियों द्वारा लगभग 7,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है। इससे 16 हजार से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही पी.एम. मित्रा पार्क में अब तक 38 कंपनियों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों की कुल राशि 21,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इससे बदनावर क्षेत्र में लगभग 55 हजार रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके लिए अब तक कुल 1,140 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। पी.एम. मित्रा पार्क का तृतीय चरण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा इकाइयों की लीज डीड एवं प्लॉट आधिपत्य की कार्यवाही तीव्र गति से संपादित की जा रही है।

पी.एम. मित्रा पार्क के द्वितीय चरण में भिलोसा इंडस्ट्रीज द्वारा 4,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए कंपनी को 200 एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है। इस इकाई से लगभग 3,500 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भिलोसा इंडस्ट्रीज मानव निर्मित धागे (मैन मेड फाइबर) के क्षेत्र में देश की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। प्रदेश में इस इकाई की स्थापना से मैन मेड फाइबर उद्योग के क्षेत्र में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा।

एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के कार्यकारी संचालक श्री हिमांशु प्रजापति ने बताया कि 30 एवं 31 जनवरी को चेन्नई में आयोजित वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के चिंतन शिविर में मध्यप्रदेश के निवेश आकर्षण मॉडल का प्रस्तुतीकरण किया गया। यह प्रस्तुतीकरण प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन श्री राघवेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित रीजनल, नेशनल एवं इंटरनेशनल रोड शो एवं कॉन्क्लेव मॉडल की सभी पी.एम. मित्रा राज्यों द्वारा सराहना की गई।

एम.पी.आई.डी.सी. का अगला लक्ष्य पी.एम. मित्रा पार्क के आसपास सामाजिक अधोसंरचना का विकास करना है। इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, खेल मैदान, अस्पताल, मनोरंजन केंद्र सहित कर्मचारियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण आवासीय वातावरण विकसित किया जाएगा। इसमें सभी आय वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पी.एम. मित्रा पार्क को एक अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें उद्योगों के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ पर्यावरण हितैषी मापदंडों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पार्क में चरणबद्ध रूप से 20 एमएलडी क्षमता का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 मेगावाट का सोलर प्लांट, ग्रीन जोन तथा जलाशयों का विकास किया जा रहा है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए पार्क में बॉयलर में कोयले के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

# यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी, एएसपी का प्रदर्शन

### 17 सूत्रीय ज्ञापन में दलित-आदिवासी और किसानों के मुद्दे उठाए

**भोपाल (नप्र)।** भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने यूजीसी के समर्थन में भोपाल में प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता अंबेडकर जयंती मैदान पर इकट्ठे हुए।

मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। संगठन ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, किसान और छात्रों से जुड़ी इन जायज मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा।

**ज्ञापन में ये 17 मुख्य मांगें-** सीएम के नाम दिए ज्ञापन में सबसे प्रमुख मुद्दा ओबीसी आरक्षण का रहा, जिसमें संगठन ने 13 प्रतिशत होल्ड आरक्षण को तुरंत प्रभाव से लागू करने और आगामी जातिगत जनगणना में पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए अलग कॉलम बनाने की मांग उठाई है।

साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के वर्षों से लंबित बैकलॉग पदों को विशेष भर्ती अभियान के जरिए भरने और पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी विनियम 2026 में संशोधन की मांग करते हुए वर्ष 2012 की तर्ज पर सख्त निर्देश जारी करने को कहा गया है ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म हो सके। संगठन चाहता है कि इक्विटी कमेटी और एंटी-डिस्क्रिमिनेशन तंत्र में इन वर्गों की कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य हो।

### किसानों और एससी, एसटी के मुद्दे उठाए

किसानों के मुद्दे पर भी भीम आर्मी और एएसपी मुखर नजर आए। उन्होंने ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के पारदर्शी सर्वे और तत्काल मुआवजे के साथ-साथ नीमच स्थित धानुका इथेनॉल प्लांट से फैल रहे प्रदूषण की स्वतंत्र जांच की मांग की है। इसके अलावा एससी-एसटी वर्ग की आवंटित जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने और 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन सहित गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की बात कही गई है।

प्रशासनिक सुधारों के तहत सीएम हेल्पलाइन की लापरवाही और चुनाव प्रक्रिया में बैलेट पेपर के विकल्प पर भी विचार करने का सुझाव दिया गया है। इस दौरान भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक सुनील बैरसिया, एएसपी कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव, प्रदेश प्रभारी विनोद यादव अम्बेडकर, सुनील अस्तेय, अनिल गुर्जर और युवा मोर्चा अध्यक्ष सतेंद्र सेंगर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

# मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे राष्ट्र व समाज प्रेरणा ले : जगतगुरू श्री राजेन्द्रदास जी महाराज

**भोपाल।** बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में श्री रेवासा धाम, श्री वृंदावन धाम के पावन सानिध्य में मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्रदास जी महाराज द्वारा गौ कथा एवं गौ आधारित प्राकृतिक खेती विषय पर दिव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि पूज्य महाराज श्री का रीवा आगमन हम सबके लिए सपना साकार होने जैसा है। उन्होंने कहा कि जब देश में बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं तो संतों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, ऐसे महान संत का हमारे बीच उपस्थित होना पूरे क्षेत्र का सौभाग्य है। इस आयोजन से क्षेत्र में अपार उत्साह और उमंग का वातावरण है। महाराज श्री की अमृतवाणी से बहने वाली कथा की रसधारा गौसंरक्षण, गौ आधारित प्राकृतिक खेती एवं सनातन मूल्यों को मार्गदर्शन देगी। उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने गौ सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि रीवा के लक्ष्मणबाग में एक हजार बेसहारा गायों के लिए गौशाला का निर्माण किया गया। इसके बाद बसामन मामा में 10 हजार गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था की गई। वर्तमान में हिनौती धाम में 25 हजार गौवंशों के संरक्षण हेतु विशाल व्यवस्था विकसित की जा रही है। यह सुनकर पूज्य महाराज श्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। बसामन मामा स्थित गौशाला के समीप 500 एकड़ का प्राकृतिक वन क्षेत्र है, जिससे गौमाता के लिए प्राकृतिक चारे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा में अनेक विकास कार्य हुए हैं, किन्तु यदि उनसे पूछा जाए कि उनका सबसे बड़ा कार्य कौन-सा है, तो वे लक्ष्मणबाग गौशाला और बसामन मामा में गौवंश विहार के निर्माण को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उन्होंने कहा कि रीवा के विकास में गौमाता की कृपा का विशेष योगदान है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि धरती को स्वस्थ रखना आवश्यक है। गौमाता के गोबर और गौमूत्र से निर्मित जीवामृत, बीजामृत जैसे उत्पाद भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं, जबकि रासायनिक खाद भूमि और मानव स्वास्थ्य दोनों को हानि पहुँचाते हैं। इसलिए गौ आधारित कृषि ही भविष्य का मार्ग है। धरती के स्वस्थ्य रहने से हम सब भी स्वस्थ्य रहेंगे। कार्यक्रम में संत श्री संतोषदास जी (सतुआ बाबा) ने कहा कि रीवा में प्रवेश करते ही यह अनुभूति होती है कि यहां का नेतृत्व शासक की तरह नहीं, बल्कि सेवक की तरह कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल की सरलता व संतों के प्रति सेवाभाव उन्हें उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ायेगी और उनके संकल्प पूर्ण होंगे। उन्होंने कहा, गाय इस पृथ्वी का सिंदूर है। उन्होंने देवहरा बाबा के वचनों का स्मरण करते हुए कहा कि जब तक पृथ्वी पर गायों का विचरण रहेगा, तब तक कलियुग प्रभावी नहीं हो सकता। इस अवसर पर राजगुरु श्री बद्री प्रपन्नाचार्य (चित्रकूट) ने भी गौ सेवा के कार्यों की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए शुभ संकेत बताया। उन्होंने कहा कि गौमाता की कृपा से यह श्रेष्ठ आयोजन हो रहा है और गौसेवा से ही सारे संकल्प पूर्ण होंगे।

# हिन्दी लेखिका संघ द्वारा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा

**भोपाल।** हिन्दी लेखिका संघ द्वारा प्रदान किये जाने वाले सम्मान व पुरस्कार इस वर्ष वार्षिक अलंकरण समारोह में आगामी 22 फ़रवरी को हिन्दी भवन श्यामला हिल्स भोपाल में दिये जाएँगें। संस्था की अध्यक्ष डॉ. साधना गंगराडे ने बताया कि इस वर्ष 4 वरिष्ठ साहित्यकारों के सम्मान के साथ 28 कृति सम्मान साहित्य की विभिन्न विधाओं में दिए जा रहे हैं। इसके तहत - कुसुम कुमारी जैन वरिष्ठता सम्मान - श्रीमती शीला श्रीवास्तव भोपाल,

डॉ फिरोजा मुजफ्फर सेवा सम्मान- डॉ कुमकुम गुप्ता भोपाल

डॉ. सुशीला कपूर हिंदी सेवी सम्मान -श्रीमती सुमन ओबेरॉय भोपाल

श्रीमती शोभा शर्मा कर्मठता सम्मान-श्रीमती राधारानी चौहान 'मानवी' भोपाल को दिया जाएगा

कृति पुरस्कारों में विभिन्न विधाओं के पुरस्कार दिये जाएँगे। जिसमें सुश्री प्रभा बरतरिया सारस्वत सम्मान स्थापित प्रभा बरतरिया द्वारा- -डॉ रंजना शर्मा भोपाल को समग्र साहित्य, श्री श्यामलाल सोनी स्मृति पुरस्कार स्थापित डॉ सुशीला कपूर द्वारा- श्रीमती प्रतिमा अखिलेश जबलपुर विधा - उपन्यास

श्रीमती उमा देवी पटेरिया स्मृति पुरस्कार स्थापित डॉ राजश्री रावत द्वारा -- संगीता चौबे-,कुबैत विधा-गजल

श्रीमती अंजना मगरे स्मृति पुरस्कार स्थापित सुनीता गजबे द्वारा - अर्चना मलैया जबलपुर, विधा - नाटक

श्री प्रेम नारायण विजयवर्गीय स्मृति पुरस्कार स्थापित श्रीमती कल्पना विजयवर्गीय द्वारा मनोरमा पंत भोपाल विधा -लघुकथा

सुश्री चंद्रावती राघव स्मृति पुरस्कार स्थापित डॉ. मालती बसंत द्वारा- ज्योत्स्ना तिवारी (भोपाल) विधा-कहानी

श्री ब्रह्मदत्त तिवारी स्मृति पुरस्कार स्थापित श्रीमती श्रद्धा तिवारी द्वारा डॉ शालिनी बड़ोले -(इंदौर) विधा -कहानी

श्रीमती गिरजावती देवी स्मृति पुरस्कार स्थापित श्रीमती श्रद्धा तिवारी द्वारा डॉ प्रतिभा द्विवेदी (भोपाल)

विधा - गीत, श्रीमती सकरी बा एवं सूरज बा स्मृति पुरस्कार स्थापित हसुमति बेन द्वारा डॉ लीला धुलधोये - (इंदौर ),लोक साहित्य

श्रीमती सुशीला जिनेश स्मृति पुरस्कार स्थापित श्री आर. डी. शरण द्वारा - डॉ संगीता पाल -गुजरात,बाल कविता

साहित्य श्री पुरस्कार स्थापित डॉ. प्रेमलता नीलम द्वारा- प्रेमलता उपाध्याय-दमोह (अध्यात्मिक पद्य)

सुश्री सुषमा तिवारी स्मृति पुरस्कार स्थापित श्रीमती श्रद्धा तिवारी द्वारा -सुषमा जादौन भोपाल ,विधा -डायरी

श्री घनश्याम दास सक्सेना स्मृति पुरस्कार स्थापित डॉ. उषा सक्सेना द्वारा डॉ नीलिमा रंजन ,भोपाल विधा -समीक्षा

श्री अरुण भार्गव स्मृति पुरस्कार स्थापित कमल भार्गव द्वारा - डॉ ऋतु जौहरी- जोधपुर विधा-यात्रा वृत्तांत

श्री द्वारका प्रसाद सक्सेना स्मृति पुरस्कार स्थापित मधु सक्सेना द्वारा डॉ नीलू शुक्ला भोपाल। शोध

श्री वासुदेव प्रसाद खरे स्मृति पुरस्कार स्थापित द्वारा दामिनी खरे अर्पणा पात्रीकर -भोपाल ,विधा-गजल

श्रीमती कस्तूरी बाई मिश्रा स्मृति स्वयंसिद्धा सम्मान स्थापित डॉ. मीनू पांडे द्वारा -डॉ करुणा राजुरकर भोपाल

श्री राधा रमण सक्सेना स्मृति पुरस्कार स्थापित मधु सक्सेना द्वारा डाँ प्रतिभा गुर्जर, भोपाल।

विधा -कहानी

श्रीमती मनोरमा द्विवेदी स्मृति पुरस्कार स्थापित डॉ.क्षमा पांडे द्वारा रेखा कापसे - नर्मदापुरम को दिया जाए गाद्य विधा -कविता। इसी प्रकार

श्री जगदीश गुप्त स्मृति पुरस्कार स्थापित डॉ.सुधा गुप्ता द्वारा -कृष्णा राजपूत-जबलपुर , विधा-कविता

श्री मुनींन्द्र मोहन स्मृति पुरस्कार स्थापित डॉ.मानवेंद्र चतुर्वेदी द्वारा -डॉ मीना शुक्ला ,भोपाल

विधा -कविता

श्री राजकुमार केसवानी स्मृति पुरस्कार स्थापित श्रीमती सुनीता केसवानी द्वारा - डॉ स्मृति उपाध्याय (भोपाल) रिपोर्टिंग

डॉ कमला सक्सेना द्वारा स्थापित नवलेखन- युवा लेखिका पुरस्कार शशि बंसल भोपाल- प्रथम प्रकाशित कृति पर दिया जाएगा

श्रीमती रामवती खरे स्मृति पुरस्कार स्थापित डॉ. ज्योत्स्ना खरे द्वारा कुमारी मुस्कान मालवीय छात्रा महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिकविद्यालय बरखेड़ा भेल भोपाल। ( हिन्दी में सर्वाधिक अंक),

श्री सुधीर अवस्थी स्मृति पुरस्कार स्थापित श्री शालू अवस्थी द्वारा -

अनामिका तिवारी जबलपुर, विधा -नाटक

श्रीमती कुलतार कौर कक्कर स्मृति पुरस्कार स्थापित सुमित नायर -द्वारा- डॉ मीना भट्ट जबलपुर, विधा -गीत

श्रीमती विजया रायकवार स्मृति पुरस्कार स्थापित निधि रायकवार द्वारा-डॉ सुमनलता श्रीवास्तव जबलपुर-पद्य श्रीमद्भगवद्गीता, बुंदेली में

टीकमगढ़ इकाई का पुरस्कार स्थापित डॉ मालती बसंत-द्वारा - डॉ रेणु श्रीवास्तव भोपाल

बुंदेली गीता गद्य के लिए दिया जाएगा।

**सोहागपुर रेल्वे स्टेशन**

# रेल मंत्री को क्षेत्रीय सांसद ने ट्रेनों के स्टापेज अमृत भारत स्टेशन योजना का किया आग्रह

**सोहागपुर।** क्षेत्रीय सांसद दर्शनसिंह ने बोहानी स्टेशन पर इन्टरसिटी एक्सप्रेस स्टापेज करवाने को लेकर सोहागपुर में सोशल मीडिया पर हुई छीछालेदर कटाक्षों के उपरांत क्षेत्रीय सांसद चौधरी दर्शनसिंह ने सोहागपुर की सुध लेते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सात ट्रेनों के स्टापेज का आग्रह किया है।इस आशय में सांसद चौधरी दर्शनसिंह के लिखें पत्र को ब्लाक भाजपा अध्यक्ष अश्विनि सरोज ने सोशल मीडिया पर डाला है। इससे नगर के वाशिंदों को राहत महसूस हुई। क्षेत्रीय सांसद चौधरी दर्शनसिंह ने सात ट्रेनों के स्टापेज करवाने का आग्रह किया है उनमें जबलपुर-इंदौर एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस,जबलपुर जन-शताब्दी एक्सप्रेस, दानापुर एक्सप्रेस, हावड़ा मेल,संघमित्रा एक्सप्रेस ,गंगा कावेरी एक्सप्रेस प्रमुख हैं। वहीं एक अन्य

पत्र में क्षेत्रीय सांसद चौधरी दर्शनसिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह में अमृत भारत स्टेशन योजना सोहागपुर को लागू करने का उल्लेख किया है।दर्शन सिंह चौधरी ने उक्त पत्र में अंकित किया है कि मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले स्थित सोहागपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह स्टेशन न केवल स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है। बल्कि आसपास के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों के हजारों यात्रियों की जीवनरेखा भी है। वर्तमान में सोहागपुर क्षेत्र में कृषि, लघु उद्योग, पर्यटन एवं धार्मिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, जिसके कारण यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तथापि, स्टेशन पर यात्री सुविधाओं, आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग, दिव्यांगजन सुविधाएँ तथा सौंदर्गीकरण आदि के क्षेत्र में व्यापक उन्नयन की आवश्यकता है।माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत देशभर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अतः विनम्र अनुरोध है कि सोहागपुर रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन योजना में सम्मिलित कर इसके सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। जिससे क्षेत्र की जनता को आधुनिक एवं सुविधायुक्त रेलवे अवसंरचना का लाभ प्राप्त हो सके। इधर सोशल मीडिया पर क्षेत्रीय सांसद चौधरी दर्शनसिंह के सोशल मीडिया पर ब्लाक भाजपा अध्यक्ष ने डालने बाद सांसद का नागरिकों ने आभार व्यक्त किया है।

# भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने व्यक्त किया शोक

**भोपाल।** भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल ने दूरदर्शन की प्रख्यात समाचार वाचिका श्रीमती सरला माहेश्वरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि श्रीमती सरला माहेश्वरी ने अपनी निष्पक्षता, सहज वाणी और पत्रकारिता के उच्च मानकों के माध्यम से वर्षों तक देशवासियों को समाचार जगत से जोड़े रखा। उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। श्री हेमंत खण्डेलवाल ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।

**पोषण आहार का काम निजी हाथों में देने पर बवाल, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना**

# अब महिलाओं का रोजगार भी छीन रही सरकार, यह कैसा महिला सशक्तिकरण : सुश्री संगीता शर्मा

**भोपाल।** प्रदेश में 1166 करोड़ रुपये के पोषण आहार कार्य को निजी हाथों में सौंपे जाने के निर्णय को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण के दावों के विपरीत तथा लाखों महिलाओं की आजीविका पर सीधा प्रहार बताया है।

सुश्री शर्मा ने कहा कि वर्षों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित पोषण आहार प्लांट न केवल स्थानीय महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रहे थे, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषण सामग्री की नियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहे थे। सीमित संसाधनों के बावजूद इन समूहों ने गुणवत्तापूर्ण कार्य कर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की थी। ऐसे में इस संपूर्ण कार्य को निजी कंपनियों को सौंपना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की भावना के प्रतिकूल है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक ओर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें ऋण उपलब्ध कराकर प्लांट स्थापित करवाती है, वहीं दूसरी ओर नीतिगत निर्णयों के माध्यम से उन्हीं इकाइयों को बंद करने की स्थिति पैदा कर देती है। इससे हजारों परिवारों की आय का स्रोत प्रभावित हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि जब महिला स्व-सहायता समूहों का मॉडल सफलतापूर्वक संचालित हो रहा था, तो उसे समाप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने आशंका जताई कि इतने बड़े वित्तीय कार्य को निजी हाथों में सौंपने से पारदर्शिता और गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों के पोषण जैसे संवेदनशील विषय को लाभ-हानि के व्यापार में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

सुश्री शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल मंचों और भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि महिलाओं को स्थायी रोजगार, सम्मानजनक आय और निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो कांग्रेस पार्टी महिला स्व-सहायता समूहों के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन करेगी।

## संक्षिप्त समाचार

### कलेक्टर ने छात्रावासों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

● **विद्यार्थियों से किया आत्मीय संवाद, परीक्षा हेतु दी शुभकामनाएं**

**बैतूल (निप्र)।** कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को जिले के छात्रावासों का निरीक्षण कर यहां उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला स्तरीय कन्या उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास, सीनियर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तथा आदिवासी महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास का भ्रमण किया। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने छात्राओं से आत्मीय संवाद करते हुए उनसे छात्रावास में आवास, भोजन, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने यह भी पूछा कि किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है तथा स्टाफ द्वारा किसी तरह की परेशानी तो नहीं की जाती। छात्राओं ने कलेक्टर श्री सूर्यवंशी को अवगत कराया कि छात्रावासों में सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं और उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने छात्राओं को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दीं और मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया।

### अवैध खनिज परिवहन पर कार्यवाही

● **खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते एक डम्पर जप्त**

**बैतूल (निप्र)।** कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशों के पालन में खनिज विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण एवं सतत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 9 फरवरी को खनि निरीक्षकबैतूल द्वारा तहसील बैतूल अंतर्गत ग्राम उड़दन-साकादेही के समीप खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए डम्पर वाहन क्रमांक MP48ZD7126 को जप्त किया गया। जप्त वाहन को थाना गंजबैतूल की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। उक्त प्रकरण में वाहन चालक/वाहन मालिक के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण तैयार किया गया है, जिसे न्यायालय अपर कलेक्टर, बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

### कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा एसपीएम का दौरा संपन्न

**नर्मदापुरम (निप्र)।** कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा प्रतिभूति कागज़ कारखाने का दौरा किया गया। उनके साथ अपर कलेक्टर (एडीएम) श्री राजीव रंजन पांडेय भी उपस्थित रहे। मिल के एजीएम श्री अमित कुमार द्वारा उनका स्वागत किया गया।

विस्तृत जानकारी देते हुए एसपीएम के डीजीएम श्री संजय भावसार द्वारा बताया गया कि इस भ्रमण के दौरान सिक्योरिटी पेपर मिल की उत्पादन प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों एवं विभिन्न तकनीकी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी उन्हें दी गई। उनके द्वारा मिल परिसर का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों से पेपर उत्पादन प्रक्रिया एवं अन्य गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली गई। इस अवसर पर कलेक्टर द्वारा मिल में किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा तथा गुणवत्ता सुधार से जुड़े प्रयासों को और सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर एसपीएम के वरिष्ठ अधिकारी सर्वश्री परीक्षित जोशी, अनूप मढ़ैया आदि भी उपस्थित थे।

### निर्माण कार्य हेतु 01 लाख 25 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी

**नर्मदापुरम (निप्र)।** सिवनीमालवा विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा की अनुशंसा पर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा विधायक निधि से 01 निर्माण कार्य के लिए कुल 01 लाख 25 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिवनीमालवा विधायक श्री वर्मा की अनुशंसा पर विधायक निधि से शासकीय सीनियर जनजातीय छात्रावास सिवनीमालवा में छात्रों एवं आमजन हेतु जिम उपस्कर स्थापना के लिए 01 लाख 25 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

# प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में शिविर आयोजित कर श्रमिकों का पंजीयन करें : कमिश्नर

**मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी 14 घंटे का अनिवार्यतः कोर्स करें संकल्प से समाधान अभियान में जिस ग्राम पंचायत एवं वार्डो से आवेदन नहीं आए उसका परीक्षण किया जाए**

## कमिश्नर ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी कलेक्टर्स को दिए निर्देश

**नर्मदापुरम (निप्र)।** नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नर्मदापुरम, हरदा एवं बैतूल जिले के कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे श्रम विभाग के माध्यम से शिविर आयोजित कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। बताया गया कि 15 हजार से कम मासिक आय वाले 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों का इसमें पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा। कमिश्नर ने निर्देश दिए की इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता श्रमिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का भी पंजीयन किया जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए। सभी सार्वजनिक जगहों पर बैनर और पोस्टर लगाकर लोगों को योजना के प्रति जागरूक किया जाए और इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाए। कमिश्नर ने मिशन कर्मयोगी के तहत शासन के निर्देशानुसार सभी राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों को 14 घंटे का अनिवार्यतः कोर्स करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी कोर्स करके प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। उन्होंने संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत अब तक प्राप्त आवेदनों एवं आवेदनों के निराकरण की स्थिति की अदयतन समीक्षा की और निर्देश दिए की जिले की जिन ग्राम पंचायतो एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों से तथा अभियान के अंतर्गत संलग्न किसी भी विभाग की योजना से संबंधित यदि आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसकी सूक्ष्मता से समीक्षा की जाए। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ऐसी ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्र के वार्ड एवं उन विभागों का अनिवार्यता परीक्षण कर ले जिससे संबंधित कोई भी आवेदन अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उल्लेखनीय है कि संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत 16 विभाग की 65 सेवाएं शामिल की गई है। नर्मदापुरम जिले में इस अभियान के अंतर्गत अब तक 25 हजार 803 आवेदन प्राप्त हुए हैं, वही हरदा जिले में 22 हजार एवं बैतूल जिले में 68 हजार 772 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर निराकरण की स्थिति की जानकारी संकल्प से समाधान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए।

कमिश्नर ने बैंक आधारित विभाग कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी, एमएसएमई, जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और निर्देश दिए की इन विभागों की जो योजनाएं बैंक स्वीकृति के लिए लगी है उन सभी में बैंक स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए और संबंधित हितग्राहियों को बैंक से स्वरोजगार के लिए ऋण राशि प्राथमिकता से दिलाई जाए।

बताया गया कि भगवान बिरसा मुंडा योजना, टंट्या मामा योजना, संत रविदास एवं डॉ भीमराव अंबेडकर योजना में हितग्राहियों को लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता से स्वरोजगार के लिए ऋण राशि दिलाई गई है। कमिश्नर ने निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। बताया गया कि नर्मदापुरम में 14 हरदा में 15 एवं बैतूल में 18 कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए बैंक द्वारा ऋण राशि स्वीकृति की गई है। कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त प्रकरणों को अटेंड करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रकरण प्राथमिकता से अटेंड कर उनका निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के नान अटेंडेंट की प्रक्रिया मान्य नहीं है। उन्होंने संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने सख्त हिदायत दी की संबल योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुग्रह सहायता राशि के आवेदन किसी भी स्थिति में पेंडिंग ना रहे। सभी आवेदनों का परीक्षण कर पात्रता अनुसार सभी आवेदन स्वीकृत करते हुए प्राथमिकता से सहायता राशि हितग्राहियों को दिलाई जाए। कमिश्नर ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं का सफल संचालन करने के निर्देश दिए और कहां की परीक्षाओं के दौरान नकल एवं किसी भी अप्रिय स्थिति की घटनाएं न होने पाए। उन्होंने उड़न दस्ता दल को नकल के प्रकरणो पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने की निर्देश दिए और कहां की करवाई का विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। गर्भवती महिलाओं की ई एन सी चेकअप के संबंध में निर्देश देते हुए कमिश्नर ने सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए की ई एन सी चेकअप के सभी प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज किया जाए।

कोई भी प्रकरण ऑफलाइन ना रहे और गर्भवती महिलाओं का पंजीयन अनिवार्य रूप किया जाए। उन्होंने इस बात पर सख्त नाराजगी जाहिर की की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों से पंजीयन की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। उन्होंने इसमें आवश्यक सुधार करने के सख्त निर्देश दिए। कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह शासन द्वारा दिए गए राजस्व वसूली के लक्ष्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करें।

### आपातकालीन वाहनों के मार्ग में बाधा बनने वाले अवैध निर्माण हटाएं, कलेक्टर-एसपी ने वार्डो का किया निरीक्षण

**बैतूल (निप्र)।** आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एवं अन्य आपातकालीन वाहनों के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन ने सोमवार को बैतूल नगर के तिलक, आजाद तथा आर्यपुरा वार्ड का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने राजस्व, पुलिस एवं नगर पालिका के अमले के साथ वार्डों का पैदल भ्रमण कर मार्गों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान आपातकालीन वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध निर्माण, मार्ग पर स्थापित हैंडपंप, बिजली के पोल, खुली नालियां एवं अतिक्रमण का मौके पर अवलोकन किया गया। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नगर पालिका के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले सभी अवैध निर्माण शीघ्र हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि मार्गों पर लगे हैंडपंप एवं विद्युत पोल को सुव्यवस्थित करते हुए आवश्यकतानुसार शिफ्ट किया जाए, ताकि किसी भी स्थिति में आपातकालीन सेवाओं को विलंब न हो। साथ ही खुली नालियों को सुरक्षित रूप से मजबूती से ढंकने के निर्देश दिए गए, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित न हो। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित वार्डों में संचालित दुकानों के संचालकों को भी समझाइश देने के निर्देश दिए कि वे दुकान का सामान सड़क या मार्ग पर न रखें। उन्होंने कहा कि मार्गो पर अतिक्रमण न केवल यातायात में बाधा बनता है, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में जान-माल के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम बैतूल डॉ. अभिजीत सिंह, एसडीओपी बैतूल श्री सुनील लाटा, तहसीलदार श्रीमती पूनम साहू, सहायक यंत्री नगर पालिका श्री नीरज धुर्वे, थाना प्रभारी कोतवाली सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

# प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना की मदद से युवा बन रहे आत्मनिर्भर

**मसाला उद्योग स्थापित कर हितग्राही श्री मदन मोहन बने उद्यमी**

**रायसेन (निप्र)।** भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना युवाओं के सपनों को हकीकत में बदल रही है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शासन द्वारा विभागीय मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता एवं वित्तीय सहयोग के माध्यम से युवाओं को उद्यम स्थापना हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जिससे वे स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। रायसेन जिले के सिलवानी विकासखण्ड के ग्राम चिचोली निवासी कृषक श्री मदन मोहन शर्मा द्वारा पीएमएफएमई योजना के तहत मसाला उद्योग स्थापित कर प्रतिमाह लगभग 30 से 35 हजार रूपए की आय प्राप्त की जा रही है। हितग्राही श्री मदन मोहन शर्मा बताते हैं कि पहले वह अपने जीवन यापन के लिए छोटी सी किराना दुकान संचालित करते थे जिससे प्रतिमाह 10,000 से 12,000 रुपए आय प्राप्त होती थी। इससे परिवार का भरण-पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाता था। जब उन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने सिलवानी विकासखंड में उद्यानिकी विभाग के अधिकारी श्री मनोज साहू से योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने मसाला उद्योग स्थापित करने के लिए योजना के तहत आवेदन किया। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण स्वीकृत होते ही उन्होंने मसाला उद्योग स्थापित किया। श्री मदन मोहन शर्मा को उद्यानिकी विभाग द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान सहायता भी प्रदान की गई है। हितग्राही द्वारा आधुनिक मशीनों के उपयोग से उच्च गुणवत्ता के उत्पाद जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर एवं अन्य मसाले ब्राण्ड ''श्री भैया जी मसाले'' के नाम से सिलवानी, गैरतगंज, रायसेन सहित अन्य जिलों में भी विक्रय कर प्रतिमाह लगभग 30 से 35 हजार रू की आय प्राप्त की जा रही है। आमदनी बढ़ने से श्री मदन मोहन शर्मा के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है, इसके लिए वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हैं।

# कृषि रथ व कृषक संगोष्ठी का आयोजन, योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी

**विदिशा (निप्र)।** कृषक कल्याण वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में विदिशा जिले के विकासखंड विदिशा अंतर्गत श्री रामलीला मेला ग्राउंड में कृषि रथ का सफल संचालन किया गया। इस अवसर पर कृषि रथ के साथ कृषक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कृषकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कृषक संगोष्ठी में पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, कृषि उपज मंडी, आत्मा परियोजना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी विभागों के अधिकारियों ने क्रमवार अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी किसानों को दी तथा योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया समझाई। पात्र कृषकों से योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने का आग्रह भी किया गया। संगोष्ठी के दौरान फसल विविधीकरण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, टोकन प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, रोग एवं कीट प्रबंधन तथा उनके निवारण के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर देते हुए इसमें उपयोग होने वाले जैविक उत्पादों को तैयार करने की विधि एवं उपयोग की प्रक्रिया भी बताई गई।

कार्यक्रम के अंत में उपसंचालक कृषि श्री के.एस. खपेड़िया द्वारा कृषकों को नरवाई प्रबंधन की शपथ दिलाई गई, जिससे मिट्टी की सेहत सुधारने एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े। प्रश्नोत्तर सत्र में कृषकों ने अपनी जिज्ञासाएँ रखीं, जिनका अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। कृषि रथ एवं संगोष्ठी के माध्यम से कृषकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समग्र जानकारी प्राप्त हुई। इस अवसर पर कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों का प्रदर्शन भी किया गया तथा उनके उपयोग एवं लाभ बताए गए। कार्यक्रम में उपसंचालक कृषि श्री के.एस. खपेड़िया, सहायक संचालक महेन्द्र ठाकुर, मंडी सचिव नीलकमल बैद्य, उद्यानिकी विभाग के सोलंकी जी, डीएमओ राखी रघुवंशी, एसएडीओ विशाल यादव सहित कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

**कलेक्टर्र के निर्देश पर मण्डीदीप में छठ घाट कलियासोत और भोजपुर में बेतवा नदी के विसर्जन स्थल पर सफाई प्रारंभ**

### इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदियों में मिलने से रोकने संबंधितों को नोटिस जारी

**रायसेन (निप्र)।** रायसेन जिले में बेतवा नदी के उद्गम स्थल झिरी और बेतवा व सहायक नदी कालियासोत के मार्ग में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को छठ घाट कलियासोत मंडीदीप और भोजपुर में बेतवा नदी विसर्जन स्थल पर सफाई कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही जिन कारखाने से इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में मिल रहा है, उनको भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी करते हुए उनको चेतावनी दी गई है कि वह अपने ड्रेनेज को नदी में मिलने से रोकने के लिए 07 दिवस में प्रबंध करें। इस कार्य में प्रशासन के साथ नगर पालिका मंडीदीप और पंचायतों की टीम में भी लगी हुई है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी सहयोग है।

# जमोनिया तालाब पर बचाव के लिए पहुंची रेस्क्यू टीमें, पानी में डूब रहे लोगों की बचाई जान

**सीहोर (निप्र)।** आज दोपहर लगभग 01 बजे जमोनिया तालाब के पास मौजूद लोगों में उस समय हड़कंप मच गया, जब तालाब में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति पानी में हाथ-पैर मारते हुए मदद के लिए पुकार रहा था। वहीं तालाब के दूसरे छोर पर बने एक छोटे टापू पर कुछ लोगों के फंसे होने की खबर से स्थिति और गंभीर हो गई। इस घटना की सूचना लोगों ने तत्काल प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही कलेक्टर श्री बालागुरू के., जिला प्रशासन, एसडीईआरएफ, एनडीआरएफ एवं होमगार्ड की संयुक्त रेस्क्यू टीमें तत्काल मौके के लिए रवाना हुईं। कुछ ही देर में मोटर बोट, रेस्क्यू उपकरण और गोताखोरों के साथ बचाव दल तालाब में उतर गया। डीप डाइविंग तकनीक का उपयोग करते हुए पानी में डूबे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं टापू पर फंसे लोगों तक मोटर बोट के माध्यम से पहुंचकर उन्हें लाइफ जैकेट पहनाई गई और सुरक्षित किनारे तक लाया गया। पूरे घटनास्थल पर बचाव कार्य युद्धस्तर पर संचालित होता रहा, जिसे देख मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम शासन के निर्देशानुसार बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित वृहद मॉक ड्रिल का हिस्सा था। इस मॉक ड्रिल में जल आपदा से निपटने की विभिन्न तकनीकों का सजीव प्रदर्शन किया गया, जिसमें डीप डाइविंग के माध्यम से डूब रहे व्यक्ति को जीवित निकालना तथा ड्राय रेस्क्यू (सूखा बचाव) जैसी तकनीकों का सफल अभ्यास शामिल था। इस दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. सहित अन्य अधिकारी इस मॉकड्रिल को देख रहे थे। मॉक ड्रिल के उपरांत एसडीईआरएफ एवं होमगार्ड के पास उपलब्ध आधुनिक बाढ़ बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में डीप डाइविंग सेट, सोनार सिस्टम, बीए सेट, मोटर बोट इंजन तथा इमरजेंसी लाइट जैसे अत्याधुनिक उपकरण प्रदर्शित किए गए, जो आपदा के समय जीवन रक्षक सिद्ध होते हैं। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने मॉक ड्रिल का अवलोकन किया तथा बचाव दल की त्वरित कार्यप्रणाली एवं तकनीकी दक्षता की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चों एवं ग्रामीणों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए तथा सीपीआर देना भी सिखाया जाए, ताकि आपातकालीन स्थिति में जनहानि को कम किया जा सके। इस अवसर पर एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, सीएसपी श्रीमती अभिनंदना शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्रीमती नीलमणी लडिया, तहसीलदार श्री भरत नायक, जनअभियान परिषद जिला समन्वयक श्रीमती पारुल उपाध्याय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रभावी नेतृत्व सीसी श्री निलेश कुमार एवं पीसी श्री महेंद्र वर्मा द्वारा किया गया।

# भाटपरेटिया में राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर सम्पन्न

**हरदा (निप्र)।** प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्राचार्य डॉ. संगीता बिले के मार्गदर्शन में ग्राम भाटपरेटिया में 02 से 08 फरवरी 2026 तक आयोजित विशेष आवासीय शिविर का समापन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शासकीय विधि महाविद्यालय, हरदा के प्राचार्य एवं स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा के प्रशासनिक अधिकारी श्री व्ही. के. विछोतिया उपस्थित रहे।

इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बसंत सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत भाटपरेटिया के सरपंच श्री सर्वेश शर्मा, सचिव सुश्री बबली तोमर व श्री तिलकराज शर्मा शामिल हुए। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ होने के पश्चात एन एस एस बैज लगाकर अतिथियों एवं ग्रामवासियों का स्वागत किया गया। छात्र इकाई के कार्यक्रम अधिकारी सुमित शर्मा ने सात दिवसीय शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि शिविर के बौद्धिक सत्रों में राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल में पदस्थ युवा अधिकारी डॉ. राजकुमार वर्मा, जिला संगठक डॉ. अरुण कुमार सिकरवार एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुनीत काशिव सहित विषय विशेषज्ञों ने पधारकर शिविरार्थियों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विछोतिया ने स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सेवा कार्यों की सराहना की। ग्राम के वरिष्ठ नागरिक श्री तिलकराज शर्मा ने विद्यार्थियों को आशीष व मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम में श्री बसंत सिंह राजपूत ने अपने उद्बोधन से सभा में ऊर्जा का संचार किया। श्री नीलेश शर्मा ने बालिकाओं के सशक्तिकरण संबंधी विचार व्यक्त किए।

राइट क्लिक

# 'वंदे मातरम्' संपूर्ण गायन : कुछ व्यावहारिक सवाल...

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

महान राष्ट्रगान 'वंदे मातरम्' के संपूर्ण गायन को लेकर गत वर्ष इस गीत की रचना की डेढ़ सौवीं वर्षगांठ से जो माहौल बनाया जा रहा था, केन्द्रीय गृह मंत्रालय का ताजा प्रोटोकॉल उसी की स्वाभाविक परिणति है। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरक शक्ति रहे इस गीत को गाया जाए, न गाया जाए, कितना गाया जाए, कहां गाया जाए, यह अब बहस का मुद्दा ही नहीं रहा है। जो नहीं गाना चाहते, वो गाने वालों की भावना का सम्मान करते हुए गीत पूर्ण होने तक खड़े रहें। अब सवाल सिर्फ इतना है कि केन्द्र सरकार ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक समारोहों में इस गीत के पूर्ण वर्जन को गाने की जो अनिवार्यता की है, वह कितनी व्यावहारिक है? क्या सरकार ने इस पक्ष पर भी गौर किया है कि हकीकत में लोग इसका कितना पालन करेंगे? कितनों को इतना लंबा गीत याद रहेगा? क्योंकि अभी 'वंदे मातरम्' के दो अंतरे गाए जाते हैं, वो भी ज्यादातर लोगों को ठीक से याद नहीं है और यह भी कि जिन देशों के लंबे राष्ट्रगीत हैं, क्या वहां भी इनका संपूर्ण गायन हो पाता है? अगर नहीं तो उसका व्यावहारिक विकल्प क्या है?

कुछ देर के लिए 'वंदे मातरम्' की राजनीतिक सरगम को नजरअंदाज करें तो संपूर्ण गीत गायन की व्यावहारिक दिक्कतें जल्द सामने आएंगी। पहला तो यह कि इस गीत का वर्तमान में प्रचलित स्वरूप दो अंतरों का है और राष्ट्रगान के रूप में इसे ही स्वीकार किया गया है। इसे गाने में 65 सेकंड लगते हैं। यदि इस गीत को संपूर्ण रूप में, जिसमें 6 अंतरे हैं, गाया जाए तो उसमें 3 मिनट 10 सेकंड लगेंगे। भारत में नियम यह है कि राष्ट्रगान अथवा राष्ट्रगीत गायन के समय उसके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े रहना होता है। ताजा प्रोटोकॉल में कहा गया है कि अब राष्ट्रगान (वंदे मातरम्), राष्ट्रगीत (जन-मन-गण) के पहले होगा। राष्ट्रगीत गाने में 52 सेकंड लगते हैं। यानी दोनो गीत गाने में कुल समय 4 मिनट 2 सेकंड का लगेगा। क्या लोग इतने समय तक सावधान की मुद्रा में खड़े रह सकते हैं? अगर वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक के बाद एक गायें जाएं तो कुल समय 1 मिनट 17 सेकंड लगता है। राष्ट्रगान तो दूर, जमीनी हकीकत तो यह है कि श्रद्धांजलि स्वरूप रखे जाने वाले दो मिनट के मौन में भी लोग स्थिर मुद्रा में नहीं रह पाते तो चार मिनट तक एक ही मुद्रा में खड़े रहना क्या आसान है? और यदि लोग इसका ठीक से पालन नहीं करते तो क्या यह राष्ट्रगान का अपमान नहीं होगा?

यहां तर्क दिया जा सकता है कि जब लोग मंदिरों में 10-10 मिनट आरती गा सकते हैं तो 4 मिनट का राष्ट्रगान गाने में क्या दिक्कत है? क्या वो इतनी देर तक सावधान रहकर अपने देशप्रेम का इजहार भी नहीं कर सकते? कहा यह भी जा सकता है कि जब बांग्लादेशी अपने राष्ट्रगीत 'आमार शोनार बांग्ला', जो 2 मिनट 56 सेकंड का है, को गा सकते हैं तो भारतीय तीन मिनट से ज्यादा के राष्ट्रगान को क्यों नहीं गा सकते? बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी पूरा ही गाया जाता है। यह गीत कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और अभी तक तो वहां का राष्ट्रगीत बना हुआ है। (नया संविधान आने पर बदला भी जा सकता है, क्योंकि वहां के कट्टरपंथी मुसलमानों को यह मंजूर नहीं है कि मुस्लिम बांग्लादेश का राष्ट्रगीत एक हिंदू द्वारा लिखा गया हो। आश्चर्य नहीं कि आने वाले समय में वहां के राष्ट्रकवि नजरूल इस्लाम का लिखा कोई गीत राष्ट्रगीत घोषित कर दिया जाए, क्योंकि नजरूल मुसलमान थे। हालांकि उनकी पत्नी हिंदू थी।)। एक और तर्क यह हो सकता है कि जब सैनिक, पुलिस, कैडेट आदि परेड के समय और स्कूली बच्चे प्रार्थना सभा में सावधान खड़े रह सकते हैं तो पांच मिनट तक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के वक्त सावधान खड़े रहने से कौन-सा पहाड़ टूट पड़ेगा?

वैसे दुनिया में शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा राष्ट्रगीत ग्रीस का 'यमनोस एइस टिन एलेफ्थेरियान' (हाइम टू लिबर्टी) है। इसमें कुल 158 अंतरे हैं। यह राष्ट्रगीत 1823 में लिखा गया था। इसे पूरा गाने में 50 मिनट लगते हैं। लेकिन इसे पूरा कभी-कभार ही गाया जाता है। आमतौर पर राष्ट्रगीत के पहले दो अंतरे ही गाए जाते हैं। इसे ही मानक वर्जन माना जाता है। इसे गाने में करीब 60 सेकंड लगते हैं।

इसी तरह दक्षिण अमेरिकी देश उरूग्वे का राष्ट्रगीत 'ओरिएंतेल्स ला पात्रिया ओ ला तुम्बा' को पूरा गाने में साढ़े चार से छह मिनट लगते हैं। लेकिन व्यवहार में इसका पहला अंतरा और कोरस ही गाया जाता है। इसमे कुछ सेकंड्स लगते हैं। दुनिया में सबसे संक्षिप्त राष्ट्रगीत जापान, जॉर्डन और सान मारिनो के हैं। ये केवल चार पंक्तियों के हैं।

वर्तमान में 'वंदे मातरम् ' के दो वर्जन ही लोकप्रिय हैं। पहला, जो गान सरस्वती लता मंगेशकर ने 'आनंदमठ' फिल्म के लिए गाया था और जो प्रयाण गीत की तरह है। 'वंदे मातरम्' और 'ऐ मेरे वतन के लोगों' ने लताजी को राष्ट्रभक्ति गीतगायन के राज सिंहासन पर अटल रूप से विराजमान कर दिया है। 'आनंदमठ' के 'वंदे मातरम्' का संगीत प्रख्यात संगीतकार हेमंत कुमार ने तैयार किया था। यह भी 2 मिनट 58 सेकंड में पूरा हो जाता है। आजादी के बाद प्रख्यात गायक पं. ओंकारनाथ ठाकुर ने तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल के आग्रह पर इस गीत को आकाशवाणी के लिए रिकॉर्ड किया था। यह धुन 'देश राग में' बांधी गई है। जबकि पिछले साल वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर उस्ताद जोहर अली ने इस गीत के हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में दो नए वर्जन भी तैयार किए हैं।

कह सकते हैं कि यहां सवाल केवल आंगिक मुद्रा का न होकर राष्ट्रप्रेम का है। सही है, लेकिन आरती गाने या ताल बजाने में किसी शारीरिक मुद्रा की अनिवार्यता नहीं होती। आप अपनी सुविधा और आस्था से किसी भी तरह भगवत भक्ति कर सकते हैं। दिलचस्प यह है कि ताजा प्रोटोकॉल में सिनेमाघरों को इससे मुक्त रखा गया है। कारण साफ है कि सिनेमाघरों में इस प्रोटोकॉल का पालन होगा, होगा या नहीं, कितना होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो लोग आज साठ पार हैं, उन्हें भली भांति याद होगा कि गुजरे जमाने में सिनेमाघरों में शो छूटने के बाद पर्दे पर राष्ट्रगीत बजता था। लेकिन अधिकांश दर्शक उसके पहले ही थियेटर से निकल जाते थे कि 52 सेकंड तक कौन खड़ा रहेगा। यह राष्ट्रगीत का अपमान ही था। इसलिए सरकार ने बाद में इसे खत्म कर दिया। राष्ट्रगीत के समय सावधान की मुद्रा में खड़े न रहना अथवा उसके गायन से पहले ही खिसक लेना, नियम विरूद्ध भले हो, लेकिन यह मानवीय प्रवृत्ति है और इसे केवल राष्ट्रगान के प्रति अरूचि, असम्मान अथवा देशद्रोह की शक्ल में नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब लोग 52 सेकंड के लिए भी रूकने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर आम लोग 4 मिनट के लिए सावधान कैसे खड़े रहेंगे? इस नियम को अनिवार्य रूप से किस सख्तीग के साथ लागू किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी, वरना यह भी संभव है कि ज्यादातर लोग (आयोजकों, अतिथियों को छोड़ दें) तो कार्यक्रम में राष्ट्रगान होने के बाद ही पहुंचें या उसके होने के पहले ही निकल लें।

माना यह भी जा रहा है कि 'वंदे मातरम्' को दो अंतरों से पूरे छह अंतरों तक लाने के पीछे पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है। भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि पहले कांग्रेस और बाद में ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने महान लेखक, कवि बंकिमचंद्र चटर्जी को अपेक्षित सम्मान नहीं दिया। उनके द्वारा रचित 'वंदे मातरम्' गीत से देवी की शक्ल में की गई मातृभूमि की वंदना का हिस्सा कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते 1937 में ही हटा दिया और केवल आरंभ के दो अंतरे राष्ट्रगान के रूप में मान्य किए गए। इसका मुख्य कारण मुसलमानों द्वारा इस गीत का विरोध करना था, क्योंकि उनका मानना है कि 'वंदे मातरम्' और विशेषकर इसके तीसरे से छठे अंतरे तक मातृभूमि के रूप में मां दुर्गा की आराधना है। और मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुका सकता। जबकि भाजपा का मानना है कि इस ओजपूर्ण गीत से संपूर्ण गायन से हिंदुओं में स्वाभिमान जागेगा। वो भगवा रंग में रंग कर भाजपा को वोट देंगे और बंगाल में पहली बार उसकी सरकार बनेगी। हालांकि मोदी सरकार इस बात से इंकार करती रही है कि वंदे मातरम् को अनिवार्य करने के पीछे कोई राजनीतिक अजेंडा है। उसका तर्क है कि यह डेढ़ सौ साल बाद 'वंदे मातरम' को उसकी मूल भावना के अनुरूप सम्मान प्रदान करने बहुप्रतीक्षित प्रयास है। एक तर्क यह भी दिया गया कि ऐसा करना जेन-जी की मांग है। यह बात अलग है कि जेन-जी के कितने लोग वंदे मातरम् के शुरूआती दो अंतरे भी ठीक से गाकर दिखा सकते हैं। हकीकत में 'वंदे मातरम्' तो छोड़िए देवनागरी वर्णमाला के 52 अक्षर भी ठीक से गिना दें तो गनीमत है। बहरहाल 'वंदे मातरम्' के संपूर्ण गायन से भाजपा को कितना राजनीतिक लाभ होगा, लोगों में देशप्रेम का स्तर किस ऊंचाई तक उठेगा, कहना मुश्किल है। वैसे भी बंगाल का राजनीतिक और सामाजिक ताना-बाना उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्यों से अलग है। यदि वंदेमातरम् का संपूर्ण गायन सत्ता वंदन तक ले जाने में मददगार हो सके तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। अगर पार्टी ममता को सत्ता से बेदखल करने में असफल रही तो हो सकता है कि 'वंदे मातरम्' के फिर से दो ही अंतरे यथावत गूंजते रहें।

## महिला से नासिक के ठग ने 2.92 लाख ठगे

### करेंसी एक्सचेंज के नाम पर की वारदात, रुपए के बदले डॉलर लेना चाहती थी पीड़िता

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल की मार्केटिंग कंपनी की महिला कर्मचारी को नासिक निवासी ठग ने करीब 2.92 लाख रुपए का चूना लगा दिया। ठग ने यह रकम करेंसी एक्सचेंज के नाम पर ली थी। पीड़िता रुपए के बदले डॉलर लेना चाहती थी। लिहाजा उसने तीन किस्तों में आरोपी को पूरी रकम दी। पैसा मिलते ही आरोपी ने अपना मोबाइल फोन ही बंद कर लिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ठगी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय विनीता प्रजापति गांधी नगर इलाके में रहती हैं। वे एक निजी मार्केटिंग कंपनी में काम करती हैं। यह कंपनी करेंसी एक्सचेंज का काम भी करती है। विनीता ने रुपए के बदले डॉलर खरीदने के लिए नासिक निवासी रविप्रकाश त्रिपाठी से संपर्क किया था।

### जल्द डालर उपलब्ध कराने का वादा किया था

रविप्रकाश और उसकी कंपनी रुपए के बदले डॉलर देती थी। दोनों के बीच जब डील तय हो गई तो विनीता ने सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच अलग-अलग किस्तों में 2 लाख 92 हजार 890 रुपए रविप्रकाश द्वारा दिए गए खाता नंबर में ट्रांसफर कर दिए। पैसे लेने के बाद उसने कहा था कि वह जल्द ही डॉलर उपलब्ध करा देगा।

## मप्र में एपस्टीन फाइल से जुड़े मामले में पहली एफआईआर

### सोशल मीडिया पर डाला पीएम को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट

**जबलपुर (नप्र)।** मध्य प्रदेश में एपस्टीन फाइल विवाद से जुड़े किसी मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। केस जबलपुर नगर निगम के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कौरव की शिकायत पर अज्ञात शख्स के खिलाफ किया गया है। 9 फरवरी को ओमती थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से 'एक्स' पर एआई जनरेटेड तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, जिनमें शहर की अलग-अलग जगहों पर कथित यूनिपोल पोस्टर दिखाए गए हैं। इन पोस्टर में एपस्टीन फाइल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एआई से तैयार आपत्तिजनक कंटेंट है। इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कौरव का कहना है कि वास्तविकता में ऐसे पोस्टर शहर में लगाए ही नहीं गए थे। इस संबंध में ओमती थाने में 12 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने धारा 197-ए बीएनएस के तहत यूथ कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

### मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंजीनियर्स की एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का किया शुभारंभ

# भवन निर्माण में उत्कृष्ट दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालीन कार्ययोजना अपनायें : मुख्यमंत्री

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि निर्माण सिर्फ ईंट-पत्थर का संयोजन नहीं, एक अभिनव कला है। इसमें उत्कृष्ट दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालिक कार्य योजना को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अब हर निर्माण कार्य में कन्सेप्चुअल और क्वालिटेटिव एप्रोच अनिवार्य रूप से दिखाई देना चाहिए। गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए हम सभी को पूरी क्षमता दक्षता से काम करना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को रवीन्द्र भवन में लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा आयोजित एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारियों, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अभियंताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता और कार्यशैली में जड़ता से बचने और बदलती तकनीकों के अनुरूप स्वयं को अद्यतन रखने के लिए कौशल संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। ऐसी कार्यशालाएं अभियंताओं की स्किल्स को रिफ्रेश करती हैं और उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में दीर्घकालिक दृष्टि, नवाचार और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पीएम गतिशक्ति योजना के माध्यम से लोक निर्माण विभाग नवाचारों को धरातल पर उतार रहा है। वर्तमान समय में हमारे इंजीनियर्स साक्षात् भगवान विश्वकर्मा के अवतार हैं। लोक निर्माण विभाग ने पिछले 2 वर्षों के कार्यों के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस अवधि में सराहनीय कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता के अंतिम अध्याय में ज्ञान और विज्ञान की बात कही गई है, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार के साथ पंच तत्वों की व्याख्या की गई है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की यह कार्यशाला आधुनिक संरचनाओं के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। हमारे इंजीनियर्स ने सांदीपनि विद्यालय सहित बड़े-बड़े अधोसंरचनात्मक विकास के निर्माण कार्य किए हैं। सड़क, पुल, स्टेडियम और भवन जैसे निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ही किये जाते हैं। विभागीय इंजीनियर्स की क्षमता संवर्धन के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स को अपना काम करने में अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आज की कार्यशाला में एमपीआईडीसी सहित देश की विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौते हुए हैं। प्रदेश में ग्रीन बिल्डिंग के विकास को लेकर सहमति बनी है।

### तकनीक, पारदर्शिता और गुणवत्ता से बदलेगा निर्माण तंत्र : लोक निर्माण मंत्री सिंह

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने क्षमता संवर्धन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि विभाग की उस निरंतर सुधार यात्रा का प्रतीक है जिसमें नई सोच, नई प्रणाली और उच्च गुणवत्ता के साथ लोक निर्माण विभाग आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब सोच बदलती है तभी व्यवस्था बदलती है, और यह कार्यशाला विभाग के नवाचारों की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में अधोसंरचना विकास को केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उसे सुशासन, पारदर्शिता, तकनीक और नागरिक सुविधा से जोड़ा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, डिजिटल इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, हरित विकास और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब विकास समन्वित सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने अधोसंरचनात्मक विकास को नई गति और दिशा दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्पष्ट संदेश है कि निर्माण केवल संरचना नहीं, बल्कि भविष्य की नींव है। समयबद्धता, गुणवत्ता, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता अब विभाग की कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोक निर्माण विभाग के लिए 293 इंजीनियर्स के पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्य जारी है। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैन्युअल 2.0 विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो सरकारी भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए एक समग्र मार्गदर्शिका का कार्य करेगा। मंत्री श्री सिंह ने पीएम गति शक्ति पोर्टल आधारित रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सड़कों, पुलों और भवनों का वास्तविक आधार प्रशिक्षित एवं सक्षम मानव संसाधन होता है। इसी उद्देश्य से विभाग ने राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर एक वर्ष का प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें प्रत्येक त्रैमास के लिए सड़क, पुल, भवन, पर्यावरण और नवीन तकनीकों जैसी थीम निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले भवनों को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप निर्मित करने के निर्देशों के पालन में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियंताओं को इस विषय पर प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है, जो विभाग की सकारात्मक कार्य संस्कृति का उदाहरण है। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए ट्री शिफ्टिंग की एक कार्यशाला भी बहुत जल्द आयोजित की जाएगी। भास्कराचार्य संस्थान ने लोक निर्माण विभाग के 500 से अधिक लोक कल्याण सरोवरों की कार्य योजना तैयार कर ली है। लोक निर्माण विभाग ने कार्यों का औचक निरीक्षण की शुरुआत की है, जिसे ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों ने अपनाया है। लोक निर्माण तकनीक, पारदर्शिता और मानवीय संवेदनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।

### निजी कंपनियों के 5 प्रतिशत से कवर हुआ आधा प्रदेश, संसद में पेश हुए आंकड़े

# मप्र के 56 प्रतिशत गांवों में बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं

**भोपाल (नप्र)।** मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी टेलीकॉम सेवाओं के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जहां एक ओर प्रदेश के आधे से ज्यादा गांव अत्याधुनिक 5 प्रतिशत नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी कंपनी बीएसएनएल अभी भी आधे से ज्यादा प्रदेश में अपनी पहुंच बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।

**56 प्रतिशत गांवों तक अब भी नहीं पहुंची पहुंच-** संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में बीएसएनएल के नेटवर्क विस्तार की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे है। मध्य प्रदेश में कुल 54,903 गांव हैं इनमें से केवल 24,394 गांवों को ही बीएसएनएल की सेलुलर सेवाओं से कवर किया जा सका है।

**नेटवर्क विहीन:** प्रदेश के लगभग 55.5 प्रतिशत (करीब 30,509 गांव) में

आज भी बीएसएनएल का सिग्नल नहीं पहुंचता है। उत्तर प्रदेश (पूर्व) जैसे सर्कल में बीएसएनएल ने 92 प्रतिशत गांवों को कवर कर लिया है, जबकि एमपी में यह आंकड़ा आधे से भी कम है।

**4 प्रतिशत टावरों का जाल और 5 प्रतिशत की तैयारी-** संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया कि बीएसएनएल वर्तमान में पूरे देश में 1 लाख स्वदेशी 4प्रतिशत टावर लगा रहा है । 15 जनवरी, 2026 तक 97,672 साइटें स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें से 95,511 साइटें ऑन-एयर हो चुकी हैं । खास बात यह है कि ये सभी उपकरण भविष्य में 5 प्रतिशत में अपग्रेड किए जा सकेंगे ।

### 5 प्रतिशत की रफ्तार : आधा मध्य प्रदेश हाई-स्पीड इंटरनेट से लैस

बीएसएनएल की सुस्ती के विपरीत, देश में 5 प्रतिशत के विस्तार ने प्रदेश में तेज रफ्तार पकड़ी है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5 प्रतिशत बाजार बन गया है। मध्य प्रदेश के 27,961 गांवों में 5 प्रतिशत नेटवर्क पहुंच चुका है. यानी प्रदेश के 51 प्रतिशत से अधिक गांव अब सुपर-फास्ट इंटरनेट जोन में हैं।

### गांवों तक 5 प्रतिशत पहुंचाने में एमपी देश में 6वें नंबर पर

टावरों का जाल- प्रदेश भर में अब तक 22,182 5 प्रतिशत बीटीएस टावर लगाए जा चुके हैं। गांवों तक 5प्रतिशत पहुंचाने के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप राज्यों की सूची में छठे (6वें) स्थान पर है।

# 55 कलेक्टर, 16 निगमायुक्त, 12 संभागायुक्त आज भोपाल में

### जनगणना की तैयारियों को लेकर ट्रेनिंग के लिए बुलाया, सीएम रहेंगे कार्यक्रम में

**भोपाल (नप्र)।** प्रदेश के सभी 55 जिलों के कलेक्टर, सभी 12 संभागों के आयुक्तों और 16 नगर निगमों के कमिश्नर शुक्रवार को भोपाल में रहेंगे। एक मई से शुरू होने वाली मकानों की गणना के अंतर्गत इन अधिकारियों को जनगणना के प्रशिक्षण के लिए भोपाल बुलाया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की मौजूदगी में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे।

गृह विभाग के सचिव और राज्य नोडल अधिकारी जनगणना अभिषेक सिंह ने इसको लेकर सभी कलेक्टरों, संभागीय आयुक्तों, नगर निगम आयुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए 13 फरवरी को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसका पहला चरण मकान गणना के रूप में इसी साल एक मई से शुरू होने वाला है। इसके लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कांफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है।

### प्रशिक्षण में दी जाएगी ये जानकारी

- जनगणना 2027 के लिए तय नीति के अंतर्गत कितने दिन में जनगणना होना है, क्या प्रोसेस होगी, क्या सवाल होंगे और डिजिटल टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं।
- जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर क्या प्रक्रिया होगी, ट्रेनिंग, फंड वितरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र, अलग-अलग इकाइयों की जनगणना में उपयोगिता बताई जाएगी।
- फील्ड एक्टिविटीज के दौरान किस तरह के चैलेंज सामने आएंगे और कैसे काम करना है?
- मोबाइल एप्स, सीएमएमएस, एचएलबीसी जैसे डिजिटल टूल्स की वर्किंग, मॉनिटरिंग की जानकारी दी जाएगी।

### सितम्बर 2025 से रिक्त है जनगणना निदेशक का पद

मध्यप्रदेश में जनगणना निदेशक का पद 30 सितम्बर 2025 के बाद से रिक्त है। तीस सितम्बर को यहां जनगणना निदेशक के रूप में काम कर रहीं भावना वालिम्बे रिटायर हो गई हैं। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार इस पद पर किसी अधिकारी की तैनाती नहीं कर सके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल होने वाली जनगणना को लेकर मकानों की गणना के लिए तारीख के बाद अब प्रश्नावली और प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी ऐलान कर दिया है। अभी एमपी के जनगणना निदेशक का चार्ज छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक के अतिरिक्त प्रभार के रूप में है।